March 2024

indiaelectionmonitor.org

Free and Fair Elections in India

Baseline Report ahead of 2024 General Election

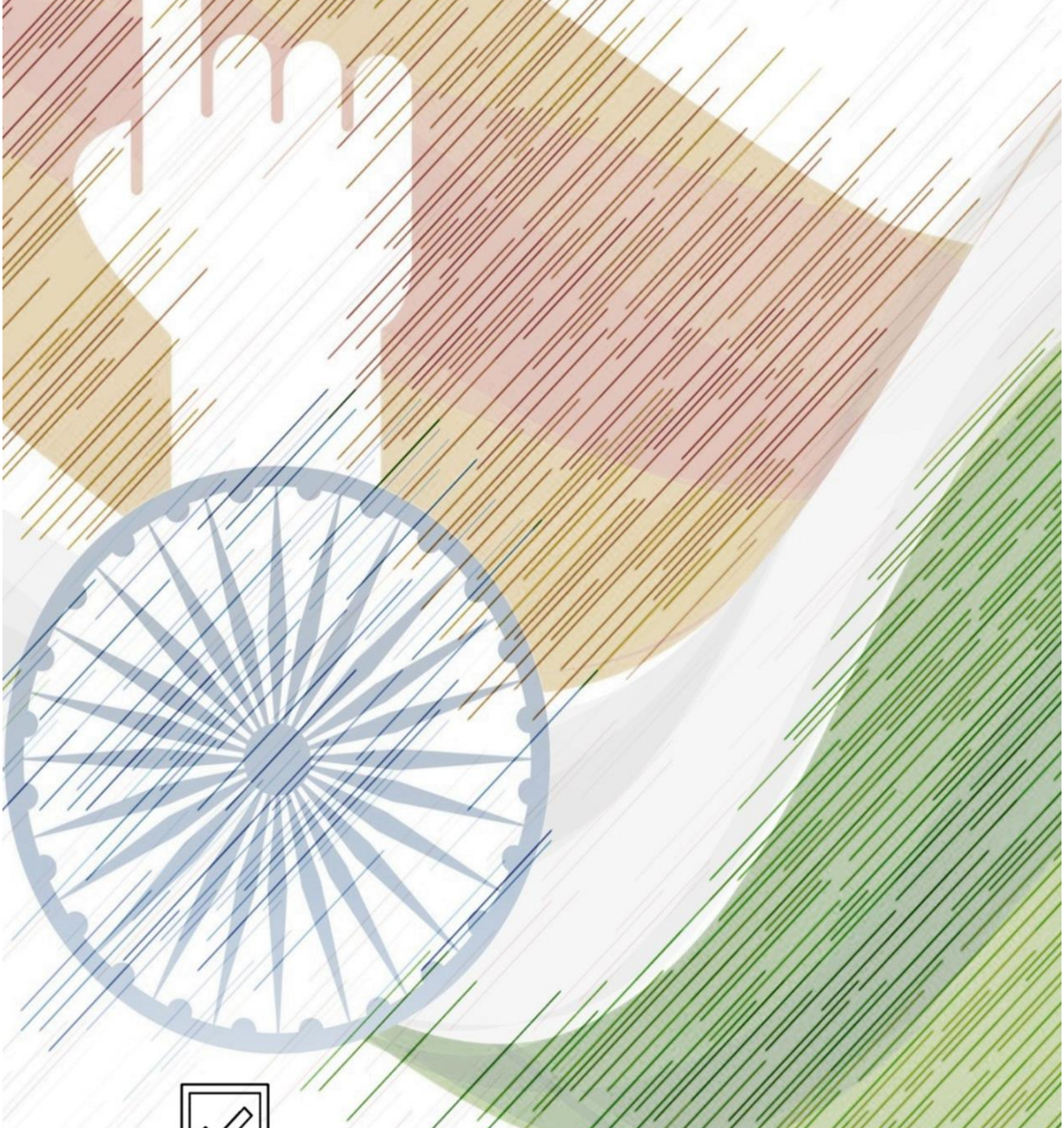

Independent Panel For Monitoring Indian Elections

चुनाव पूर्व रिपोर्ट

भारतीय चुनाव-2024 निगरानी पर स्वतंत्र पैनल - 2024

1. प्रोफेसर नीरा चंडोके, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में नेशनल फेलो और सेवानिवृत्त। प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

2. डॉ. थॉमस डैफेन, दार्शनिक और इतिहासकार; विश्व बौद्धिक बुद्धि मंच के अध्यक्ष; निदेशक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज एंड ग्लोबल फिलॉसफी (फ्रांस और यूके); संयोजक, कॉमनवेल्थ इंटरफेथ नेटवर्क

3. श्री सखावत हुसैन, बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त

4. डॉ. हरीश कार्निक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी, कानपुर, भारत

5. डॉ. सबस्टियन मॉरिस, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद, भारत

6. प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, प्रोफेसर और अध्यक्ष, दक्षिण एशिया की आधुनिक राजनीति, दक्षिण एशिया संस्थान, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी

मार्च 2024

कार्यकारी सारांश

संकेताक्षर की सूची

तालिकाओं और ग्राफ़ की सूची

1. भारतीय चुनावों की निगरानी पर स्वतंत्र पैनल - 2024

2. परिचय: क्या भारत के आम चुनाव 2024 स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे?

पैनल की रिपोर्ट

3. क्या भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है?

3.1 परिचय

3.2 वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध: मतदाता सूची से बहिष्कार

3.3 जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को नकारना

3.4 प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए चुनावी सीमाएँ खींचना

4. क्या भारतीय मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प हैं?

4.1 परिचय

4.2 राजनीतिक बहुलवाद को नकारना: चुनावी बांड और मजबूत हथियार रणनीति

4.3 मतदान संचालन में समझौता: ईवीएम के खिलाफ मामला

5. क्या भारतीय मतदाता सूचित विकल्प चुनने में सक्षम हैं?

5.1 परिचय

5.2 विपक्ष को बंद करने के लिए वायु तरंगों पर एकाधिकार स्थापित करना

5.3 विपक्षी सदस्यों और असहमत लोगों के खिलाफ कार्रवाई

5.4 सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, घृणास्पद भाषण और दुष्प्रचार

6. क्या भारत में चुनावों का संचालन स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण है?

6.1 परिचय

6.2 भारत का चुनाव आयोग - भारतीय चुनावों का मध्यस्थ

6.3 ईसीआई द्वारा अपने संवैधानिक अधिदेश का निष्पादन

6.4 चुनावी उपाय और चुनावी न्याय

6.5 भारत का चुनाव आयोग - मध्यस्थ, समझौता?

7. निष्कर्ष: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और भारत के लोकतंत्र का भविष्य

8. कार्रवाई के लिए कॉल

संदर्भ

अनुबंध I: स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक चुनाव: अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मानक

कार्यकारी सारांश

1. भारत में लगभग 970 मिलियन मतदाता संसद के निचले सदन - लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अप्रैल-मई 2024 में अपना वोट डालने जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों से नागरिक समूह अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे, इसलिए वास्तविक नहीं होंगे। विशिष्ट क्षेत्रों में, चुनाव से इनकार किए जाने की संभावना के साथ-साथ कमजोर समूहों को मतदान से बाहर किए जाने को लेकर भी नाराजगी है। और नागरिक समाज समूह राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने और हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं उठा रहे हैं।

2. हम स्वतंत्र विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं का एक समूह हैं, जिन्होंने खुद को भारतीय चुनावों की निगरानी के लिए स्वतंत्र पैनल (आईपीएमआईई) - 2024 के रूप में गठित किया है, जो घरेलू नागरिक समाज समूहों द्वारा इन चुनौतियों से जुड़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया गया है, ताकि

नागरिक समूहों का समर्थन किया जा सके। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक आम चुनाव (जीई) 2024 सुनिश्चित करना।

3. वर्तमान रिपोर्ट हमारा आकलन है, जो GE 2019 के बाद के अनुभव पर आधारित है, कि क्या भारतीय नागरिक सार्वभौमिक मताधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हैं; निःशुल्क विकल्प की पेशकश की जाती है; और इसे सूचित तरीके से बना सकते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सार हैं, जो लोगों की इच्छा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं, जो स्वयं एक प्रतिनिधिनात्मक लोकतंत्र की आधारशिला हैं।

4. इस 'चुनाव पूर्व' रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम अधिसूचित होने के बाद जीई 2024 चुनाव चक्र के हमारे अवलोकन के लिए आधार रेखा के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं।

क्या भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है?

- **i.** एक अनुमान के अनुसार, 2019 में देश भर में 30 मिलियन से अधिक मुस्लिम मतदाता और 40 मिलियन दलित मतदाता मतदाता सूची से गायब थे। ईसाइयों के साथ-साथ आंतरिक प्रवासियों और बेघरों के बहिष्कार की भी इसी तरह की रिपोर्टें हैं।
- ii. जम्मू और कश्मीर में मतदाताओं की संख्या लगभग 10 मिलियन है, उनको 2018 के बाद से राज्य विधानसभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान करने का मौका नहीं मिला है, जिससे वे मताधिकार के अपने मूल अधिकार से वंचित हो गए हैं।
- iii. असम में, ईसीआई द्वारा चिह्नित संदिग्ध मतदाता (डी-वोटर), जिनकी संख्या लगभग 100,000 है, जिनमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुस्लिम हैं, साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर किए गए विभिन्न पृष्ठभूमि के 1.9 मिलियन व्यक्ति का अधिकर खतरे में हैं। उन्हे वोट देने से इनकार किया जा रहा है.
- iv. जम्मू-कश्मीर और असम, दोनों में बड़ी मुस्लिम आबादी है, हाल ही में परिसीमन अभ्यास को भविष्य के चुनावी मुकाबलों में मुसलमानों को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए चिह्नित किया गया है। संसद में पहले से ही निराशाजनक मुस्लिम प्रतिनिधित्व (लगभग 15% की जनसंख्या हिस्सेदारी के मुकाबले 4.2%) और राज्य विधानसभाओं में, और First Past the Post चुनावी प्रणाली के साथ, यह आगे चलकर समान मताधिकार के संवैधानिक वादे से समझौता करता है।

क्या भारतीय मतदाताओं के पास 'वास्तविक विकल्प' है?

- **i.** भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने व्यवस्थित रूप से विपक्षी दलों को निशाना बनाया है, जबकि उसने भाजपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है।

● केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई आपराधिक मामले शुरू किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2014 के बाद से राजनीतिक दलों के खिलाफ सभी मामलों में से 90% विपक्षी दलों के खिलाफ हैं।

● 2017 और 2023 के बीच, बीजेपी ने कथित तौर पर चुनावी बांड योजना (EBS) के माध्यम से सभी पार्टियों द्वारा जुटाए गए $1.45 बिलियन में से अनुमानित $800 मिलियन पर कब्ज़ा कर लिया। यह EBS की अपारदर्शी प्रकृति और इसके संचालन पर भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन के नियंत्रण के कारण संभव हुआ है।

● EBS को गैरकानूनी घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत है, लेकिन पहले से ही एकत्र किए गए धन का मतलब है कि 2024 के चुनावों में भाजपा के पास पहले से ही एक निर्णायक संसाधन लाभ है।

● बांह मरोड़ने के भी सबूत हैं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आपराधिक जांच का सामना करने के बाद 30 कंपनियों ने बीजेपी को 40 मिलियन डॉलर का दान दिया।

ii. भारत के चुनाव आयोग ने भारत में चुनावों में पेपर बैलेट के स्थान पर उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खामियों के बारे में चिंताओं को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। ईवीएम के डिजाइन और कार्यान्वयन, साथ ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सत्यापन दोनों के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्हें पूर्ण स्वतंत्र समीक्षा के लिए भी नहीं खोला गया है। हालाँकि अब ईवीएम में वोटर वेरिफाइड पेपर और ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) लगाए गए हैं, लेकिन नतीजों को सार्वजनिक करने से पहले डाले गए वोटों या गिने गए वोटों को सत्यापित या ऑडिट करने के लिए किसी पेपर पर्चियों की गिनती या मिलान नहीं किया जाता है। यह हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट डालने के खिलाफ गारंटी भी प्रदान नहीं करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, शुरू से अंत तक सत्यापन की कमी के कारण, वर्तमान ईवीएम-वीवीएपैट प्रणाली मजबूत नहीं है और इसलिए लोकतांत्रिक चुनावों के लिए अनुपयुक्त है।

क्या भारतीय मतदाता सूचित विकल्प चुनने में सक्षम हैं?

I. विपक्षी राजनीतिक दलों को छोड़कर, भाजपा ने सूचना क्षेत्र पर एकाधिकार जमा लिया है।
और सूचना के मुक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी पहले से ही व्यापक शक्तियों को और गहरा कर दिया है।

● भारतीय मीडिया तेजी से कुछ कॉर्पोरेट हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। यह दिखाया गया है कि इन संस्थाओं का भाजपा से सीधा राजनीतिक संबंध है। उनकी प्रोग्रामिंग भी खुलकर पार्टी का समर्थन करती है. सरकार की ओर से विज्ञापन समर्थन पर बढ़ती निर्भरता ने मीडिया को भाजपा सरकार की राह पर चलने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया है।

● बीजेपी समर्थक अभिनेता भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. भाजपा के आईटी सेल पर अपने शीर्ष

नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण के तहत जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है।

II. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों ने भी स्वतंत्र मीडिया और तथ्य-जांचकर्ताओं पर लगाम कसना तेज कर दिया है, जिसमें आतंकवाद विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग भी शामिल है।

III. ऐसा लगता है कि भाजपा और सहयोगी समूहों ने चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को दोगुना कर दिया है - जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, और केंद्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए नियमों की घोषणा करना, ऐसे मामले हैं। प्रभावशाली नेताओं द्वारा ऑनलाइन और भौतिक स्थानों पर अमानवीय बयानबाजी के साथ-साथ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का सीधा आह्वान जारी है।

IV. अत्यधिक सांप्रदायिक माहौल की पृष्ठभूमि में, एआई-संचालित डीपफेक और अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न उभरते खतरे विशेष रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि हम चुनावों में प्रवेश कर रहे हैं।

क्या भारत में चुनाव का संचालन स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण है?

I. पर्याप्त शक्तियों का आनंद लेने के बावजूद, भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मौजूदा कानूनों, नियमों और मॉडल कोड को लागू करना चाहता रहा है। आरोप शामिल हैं

- चुनाव की तारीखों और कैलेंडर की घोषणा में सरकार समर्थक पूर्वाग्रह
- आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को सख्ती से लागू करने में विफलता, जिसमें सांप्रदायिक चुनाव भाषणों, विशेषकर शीर्ष भाजपा नेताओं के भाषणों के खिलाफ दिशानिर्देश शामिल हैं।
- प्रमुख चिंताओं पर हितधारकों, साथ ही राजनीतिक दलों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने में विफलता, जिसमें मतदाता सूची से गलत बहिष्करण, जहां आवश्यक हो वहां चुनाव नहीं कराना, ईवीएम-वीवीपीएटी में एंड-टू-एंड सत्यापन की कमी और एमसीसी का पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन शामिल है।

II. ईसीआई के खराब प्रदर्शन के पीछे केंद्रीय कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्रता की कमी प्रतीत होती है। ईसीआई की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल के बदलावों से सत्तारूढ़ दल को एक तरह से वीटो का अधिकार मिल गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पहले से ही कमजोर व्यवस्था के लिए यह एक बड़ा झटका है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगियों के लिए खेल का मैदान बेहद असमान हो गया है। ईसीआई से हाल ही में नेतृत्व के इस्तीफे से इस आशंका को और बल मिलता है कि जीई 2024 की देखरेख भाजपा के अधीन ईसीआई द्वारा की जाएगी।

कारवाई की हाकल:

- भारत के चुनाव आयोग को: (i) निष्पक्ष रहना चाहिए, और 2024 के आम चुनावों से समझौता नहीं करना चाहिए, (ii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल द्वारा प्राप्त वित्तीय, मीडिया

और अन्य लाभों पर अंकुश लगाया जाए; (iii) उन शिकायतों पर ध्यान दें जहां वे नागरिकों के सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार और एमसीसी के उल्लंघन से संबंधित हों।

- सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए: स्वतंत्रता, संघ, सभा, अभिव्यक्ति
- राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए और अपने अभियानों में सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं की अपील नहीं करनी चाहिए।

संकेताक्षर की सूची

- AAP: आम आदमी पार्टी
- बीजेपी: भारतीय जनता पार्टी
- CAA: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019
- सीबीआई: केंद्रीय जांच ब्यूरो
- सीसीई: चुनाव के लिए नागरिक आयोग
- सीईसी: मुख्य चुनाव आयुक्त
- मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री
- ईसीआई: भारत निर्वाचन आयोग
- ईडी: प्रवर्तन निदेशालय
- ईएमबी: चुनावी प्रबंधन निकाय
- ईवीएम: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें
- एफसीआरए: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
- एफपीटीपी: फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
- जीई: आम चुनाव
- ICCPR: नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध
- INC: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर
- एलजी: लेफ्टिनेंट-जनरल
- एमसीसी: आदर्श आचार संहिता
- विधायक: विधान सभा के सदस्य
- सांसद: संसद सदस्य
- एनडीटीवी: नई दिल्ली टेलीविजन
- एनआरसी: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
- पीएम: प्रधानमंत्री
- आरपीए: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
- एससीआई: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- SC: अनुसूचित जाति
- ST: अनुसूचित जनजाति

- यूडीएचआर: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
- संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र
- यूपी: उत्तर प्रदेश
- केंद्रशासित प्रदेश: केंद्र शासित प्रदेश
- वीवीपीएटी: मतदाता सत्यापित पेपर और ऑडिट ट्रेल

तालिकाओं और ग्राफ़ की सूची

तालिका 1: भारत में चुनाव निगरानी समूहों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ
तालिका 2: चुनाव अधिकारियों और उनकी स्वायत्तता की तुलना - भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील
तालिका 3: प्रमुख चुनावी और लोकतंत्र संकेतक - भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील

ग्राफ़ 1: वी-डेम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की गिरावट

भारतीय चुनावों की निगरानी पर स्वतंत्र पैनल - 2024

पैनल के सदस्य:

1. प्रोफेसर नीरा चंडोके, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में नेशनल फेलो और सेवानिवृत्त। प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत
2. डॉ. थॉमस डैफेन, दार्शनिक और इतिहासकार; विश्व बौद्धिक बुद्धि मंच के अध्यक्ष; निदेशक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज एंड ग्लोबल फिलॉसफी (फ्रांस और यूके); संयोजक, कॉमनवेल्थ इंटरफेथ नेटवर्क
3. श्री सखावत हुसैन, बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त
4. डॉ. हरीश कार्निक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी, कानपुर, भारत
5. डॉ. सबस्टियन मॉरिस, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद, भारत
6. प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, प्रोफेसर और अध्यक्ष, दक्षिण एशिया की आधुनिक राजनीति, दक्षिण एशिया संस्थान, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी

1 परिचय

क्या भारत के आम चुनाव 2024 स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे?

अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) के आम चुनाव (जीई) 2024 से पहले, नागरिक समूह मतदान प्रक्रिया की पवित्रता के बारे में बहुत चिंता और आशंका की रिपोर्ट कर रहे हैं, और क्या नागरिक को वोट दिया जाएगा। मुफ़्त और वास्तविक विकल्प। विशिष्ट क्षेत्रों में और विशिष्ट कमजोर समूहों के बीच, सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार से इनकार को लेकर भी पीड़ा है। देश भर में नागरिक समूह रिपोर्ट कर रहे हैं कि मतदाताओं के बीच चिंताएं चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता से समझौता किए जाने की ओर इशारा करती हैं, जिससे सभी नागरिकों के चुनावों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के अंतर्निहित अधिकार प्रभावित होते हैं। अंततः डर यह है कि लोगों की स्वतंत्र इच्छा बाधित होने का जोखिम है।

भारत में चुनाव निगरानी समूह इन चिंताओं को दूर कर रहे हैं, भारत में चुनावों की अखंडता के बारे में, और क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेंगे, खासकर 2019 में पिछले आम चुनावों के बाद से। इनमें चुनाव के लिए नागरिक आयोग (सीसीई) शामिल है। सीसीई और अन्य समूहों ने चुनाव के संचालन को लेकर कई प्रक्रियात्मक और वास्तविक चिंताएं उठाई हैं। इनमें मतदाता सूची की अखंडता और समावेशिता के बारे में प्रश्न शामिल हैं - और इसमें वंचित समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों के कथित महत्वपूर्ण बहिष्कार शामिल हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ कई मुद्दे उठाए हैं, जिनका उपयोग भारत में कागजी मतपत्रों के स्थान पर किया जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईवीएम मतदान मतदाता की आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान और यह सत्यापित करने की क्षमता है कि उनका वोट डाला गया है। जैसा कि इरादा था, कास्ट के रूप में दर्ज किया गया, और रिकॉर्ड किए गए के रूप में गिना गया। यह हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट इंजेक्शन के खिलाफ गारंटी भी प्रदान नहीं करता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी बांड योजना के माध्यम से अब तक सबसे अधिक दान प्राप्त किया है, जिससे पार्टी के वित्त में अपारदर्शिता बढ़ गई है और चुनावों में बड़े धन की भूमिका मजबूत हो गई है, जिससे समान अवसर भी क्षीण हो गए हैं। उन्होंने व्यापक स्तर के अभियानों और विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर सांप्रदायिक विभाजन के व्यवस्थित निर्माण पर भी अफसोस जताया है। और उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को लागू करने में निरंतरता की कमी और अपने विशाल अधिकार का उपयोग न करने सहित समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नियमों और मानदंडों को लागू करने के अपने कार्य में विफल रहने का आरोप लगाया है। पूरी तरह से. अप्रैल-मई 2024 में आगामी आम चुनावों से पहले, भारत में नागरिक समाज समूह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बिगड़ती स्थिति पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह भारत में चुनावी अखंडता को खतरे में डाल सकती है, जिसे सुधारा नहीं जा सकेगा।

इन चिंताओं को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने वर्तमान में चल रहे 55वें मानवाधिकार परिषद में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में व्यक्त किया है।

960 मिलियन मतदाताओं वाले भारत में, आगामी चुनाव अपने पैमाने में अनोखा होगा। मैं देश की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपराओं और इसकी महान विविधता की प्रशंसा करता हूं। हालाँकि, मैं नागरिक क्षेत्र पर बढ़ते प्रतिबंधों से चिंतित हूँ - मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कथित आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है - साथ ही अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और भेदभाव से भी। चुनाव-पूर्व संदर्भ में एक खुला स्थान सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सभी की सार्थक भागीदारी का सम्मान करता हो।

इन चुनौतियों से निपटने और उनका जवाब देने के लिए ही हमने, स्वतंत्र विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं के एक छोटे समूह ने खुद को भारतीय चुनावों की निगरानी के स्वतंत्र पैनल (आईपीएमआईई) - 2024 के रूप में गठित किया है। हम बहुराष्ट्रीय पृष्ठभूमि और विषयों से आए हैं, सभी को बहुत गर्व है। और दुनिया भर में समावेशी लोकतंत्र के लिए भारत के वादे की सराहना। हम हाल के घटनाक्रमों से समान रूप से चिंतित हैं जो उस वादे को ख़तरे में डाल सकते हैं। हम स्थानीय नागरिक समाज के प्रयासों का समर्थन करने, आगामी चुनावों का निरीक्षण करने और सार्वजनिक रूप से चिंताओं को उठाने के लिए फरवरी 2024 में एक साथ आए।

आईपीएमआईई स्वीकार करता है कि भारत की चुनावी राजनीति में लोकतांत्रिक पहलू हैं, भले ही बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने वाली सत्तावादी प्रवृत्ति तेजी से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उस ताने-बाने की जगह ले रही है जिसने 1947 में आजादी के बाद से भारत के धर्मों की विविधता और सांस्कृतिक आधारों को आवाज दी थी। यदि मतदाता की स्वतंत्र पसंद के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता में और गिरावट आती है, तो भारत एक पूर्ण विकसित बहुसंख्यकवादी और सत्तावादी राज्य में बदल सकता है। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां से उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में स्वस्थ सुधार हो सकता है। अन्यथा, भारत अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता से मुकर जाएगा, और बहुसंख्यक-सत्तावादी व्यवस्था की ओर उतर जाएगा।
2024 के चुनावों में भारत के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के संबंध में हमारी चिंताओं में से एक यह है कि सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ निकायों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा इसे पारदर्शी रूप से देखा जाना चाहिए, कि भारतीय लोकतांत्रिक मानक स्वीकार्य स्तर से नीचे नहीं गिरे हैं। संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सदस्य के रूप में, जब चुनावी अखंडता की गारंटी की बात आती है तो भारत के पास कुछ वैधानिक कर्तव्य हैं। हम चिंतित हैं कि ईसीआई, मतदान के लिए ईवीएम तंत्र की अखंडता सहित, उठाई गई वैध चिंताओं से जुड़ने से इनकार कर रहा है, लेकिन आगामी मतदान प्रक्रिया की मजबूती की गारंटी देने में विफल रहा है। चुनाव, जो प्रामाणिक लोकतंत्र का बहुत बड़ा आधार है। जिन महत्वपूर्ण निकायों के साथ हम संपर्क में हैं, और जिनकी विशेषज्ञता हमारी चिंताओं के संबंध में स्वतंत्र रूप से मांगी जा रही है, उनमें निम्नलिखित हैं: ऐस इलेक्टोरल नॉलेज नेटवर्क; संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों का विभाग - चुनावी सहायता प्रभाग; ब्रिज परियोजना-लोकतंत्र, शासन और चुनाव में संसाधन निर्माण; राष्ट्रमंडल चुनावी नेटवर्क; इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस); इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आई-आईडीईए)। जब हम 2024 में चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं तो दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और हम, आईपीएमआईई के रूप में, यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत चुनावी अखंडता के उच्चतम मानकों के अनुरूप हो, और यदि यह तकनीकी या राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर हम इन मामलों पर जोर देना चाहते हैं और जनसंचार माध्यमों में केवल यह दिखावा करने के लिए चुप्पी साधने की साजिश को अनुमति नहीं देना चाहते कि ये वास्तविक मुद्दे नहीं हैं, जबकि दुनिया भर के अधिकांश विशेषज्ञ निगरानी निकायों के लिए, 2024 में भारत की चुनावी अखंडता का मुद्दा वास्तविक चिंता है।

हमारी आशा है कि 2024 के चुनाव चक्र के दौरान हमारी निगरानी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, वह राजनीतिक दलों को हमारे द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं का जवाब देने के लिए प्रेरित करेगी, उन्हें मौजूदा कानूनों, प्रक्रियाओं और मानदंडों और चुनाव अधिकारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। भारत में, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अगली संसद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे।

मानक:

अपने काम के आधार के रूप में, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करेंगे, विशेष रूप से वे जो मानवाधिकारों पर आधारित हैं।

जैसा कि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, मिशेल बाचेलेट (2021) ने नोट किया था:
सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने का लोगों का अधिकार एक मौलिक अनिवार्यता है। वास्तविक और विश्वसनीय चुनाव लोगों के लिए शासन में भाग लेने और उनकी आवाज़ सुनने का सबसे सम्मोहक और प्रभावी तरीका है। वास्तविक और विश्वसनीय चुनाव एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा पोषित होते हैं जो आपस में जुड़े मानव अधिकारों की सुरक्षा से बना होता है: कानून का निष्पक्ष शासन; और मौलिक स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे आवश्यक अधिकारों के लिए सम्मान, जो लोगों को स्वतंत्र और सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है।

चुनाव सहित सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून द्वारा संरक्षित एक मानवाधिकार है। इसकी गारंटी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) और संधि प्रावधानों, मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) द्वारा दी गई है। इनकी गारंटी भारतीय संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) सहित विधानों द्वारा भी दी गई है। अन्य मानवाधिकार चुनावी प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए और उनका आनंद लिया जाए, विशेष रूप से समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिकार। यदि मतदान करने और निर्वाचित होने के अधिकार का सार्थक ढंग से प्रयोग किया जाना है तो यह एक प्रभावी उपाय है। ICCPR के अलावा, इन्हें भारतीय कानून में भी गारंटी दी गई है, जिसमें भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में निहित मानदंड हैं, जिनमें समान स्तर के खेल के मैदान और चुनाव अधिकारियों की भूमिका सुनिश्चित करना शामिल है। भारत के आम चुनाव 2024 की हमारी निगरानी, इन अधिकारों से सूचित होगी और उन पर आधारित होगी।

कार्यप्रणाली:

हम मतदाता पंजीकरण, प्रचार, मतदान और गिनती प्रणाली और प्रक्रिया और एमसीसी के कार्यान्वयन सहित जीई-2024 के सभी पहलुओं की निगरानी करेंगे। हमारी रिपोर्ट प्रक्रिया में निहित किसी भी अनियमितता या कदाचार को उजागर करेगी और उनके तत्काल सुधार की वकालत करेगी। लक्ष्य यह है कि जैसे-जैसे चुनाव सामने आते हैं, उन पर नज़र रखी जाए, रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और चिंताएँ उठाई जाएँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रहें; लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करें और भारतीय नागरिकों के चुनावी अधिकारों की रक्षा करें।

चुनावों के अवलोकन में, हम अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास द्वारा निर्देशित होंगे। चुनाव निगरानी गैर-पक्षपातपूर्ण पर्यवेक्षकों को तैनात करने की एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अवलोकन के लिए सिद्धांतों की घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अवलोकन के लिए आचार संहिता चुनाव निगरानी के लिए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। आचार संहिता में पर्यवेक्षकों के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं जैसे चुनाव प्रक्रिया में बाधा न डालना, अवलोकन की सटीकता के साथ-साथ निष्कर्ष निकालने में व्यावसायिकता बनाए रखना आदि। हमारी निगरानी पक्षपातपूर्ण होगी और बूथ पर आधिकारिक चुनाव पर्यवेक्षकों या मतदान एजेंटों के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

हमारे आउटपुट को रिपोर्टों के एक सेट के रूप में नियोजित किया गया है जिसे हम व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं। पहली, वर्तमान रिपोर्ट, उस मुख्य रिपोर्ट की प्रस्तावना के रूप में है जिसे हम 2024 के चुनाव संपन्न होने और परिणामों की घोषणा के ठीक बाद प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। यह 'चुनाव-पूर्व' रिपोर्ट पिछले वर्षों के राज्य विधानसभा चुनावों के अलावा, 2019 के आम चुनावों सहित हाल के चुनावों के अनुभव पर आधारित है। यह चुनाव प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता के बारे में घरेलू चुनाव निगरानी समूहों, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और मीडिया द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं पर बात करता है। अंतिम रिपोर्ट हमारा आकलन होगी, जो आम चुनाव-2024 के अवलोकन पर आधारित होगी।

तालिका 1: भारत में चुनाव निगरानी समूहों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ
(स्रोत: सीसीई, एडीआर, और मीडिया रिपोर्ट)

विषय	**विवरण**
मतदाता बहिष्करण	मतदाता सूची की अखंडता और समावेशिता के बारे में सवाल उठाए गए हैं - वंचित समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों के महत्वपूर्ण बहिष्करण की सूचना मिली है। चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चल रहा है, जिससे भारत में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव का डर भी पैदा हो रहा है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के चुनाव नियामक के कदमों के साथ-साथ, संभावित डेटा लीक, धोखाधड़ी और चोरी के लिए भी आलोचना की जा रही है।
ईवीएम	1998 से, भारत कागजी मतपत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की ओर चला गया। मतदान प्रक्रिया में ईवीएम की खामियों को लेकर कई मुद्दे उठाए गए हैं। ईवीएम के डिजाइन और कार्यान्वयन, साथ ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सत्यापन दोनों के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। उन्हें पूर्ण स्वतंत्र समीक्षा के लिए भी नहीं खोला गया है। हालांकि हर ईवीएम में वोटर वेरिफाइड पेपर एंड ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) लगा होता है, लेकिन नतीजों को सार्वजनिक करने से पहले डाले गए वोटों या गिने गए वोटों को सत्यापित या ऑडिट करने के लिए किसी भी कागज की पर्चियों की गिनती और मिलान नहीं किया जाता है। इसलिए ईवीएम मतदान 'लोकतंत्र सिद्धांतों' की आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, यानी, प्रत्येक मतदाता के पास यह सत्यापित करने का प्रत्यक्ष ज्ञान और क्षमता है कि उनका वोट उनके इरादे के अनुसार डाला गया है, डाले गए के रूप में दर्ज किया गया है, और रिकॉर्ड के रूप में गिना जाता है। यह हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट इंजेक्शन के खिलाफ गारंटी भी प्रदान नहीं करता है। एंड-टू-एंड (ई2ई) सत्यापन की अनुपस्थिति के कारण, वर्तमान ईवीएम/वीवीएपीएटी प्रणाली मजबूत नहीं है और इसलिए लोकतांत्रिक चुनावों के लिए अनुपयुक्त है।
पार्टी वित्त	भारत में चुनाव दुनिया में सबसे महंगे हैं - 2019 के आम चुनावों में 7.2 बिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यह 2014 के आंकड़े का दोगुना था। यह राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत ही असमान खेल का मैदान भी है। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2019 के खर्च का पूरा 45% हिस्सा लिया। (उसकी जीती हुई 303 संसदीय सीटों में से प्रत्येक के लिए 10.7 मिलियन डॉलर)। समस्या का एक हिस्सा चुनावी बांड योजना है - जो पार्टी फंड में गुमनाम दान की अनुमति देती है। अब तक इनमें से अधिकतर चंदा बीजेपी को मिला है. चुनावी बांड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2024 में रद्द कर दिया था, की अपारदर्शिता बढ़ाने और चुनावों में बड़े पैसे की भूमिका को मजबूत करने और समान स्तर के खेल के मैदान को ख़राब करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी।

अपराधीकरण	बड़े पैसे ने बड़े पैमाने पर 'मतदाताओं की खरीद' और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के साथ चुनावी प्रक्रिया का अपराधीकरण कर दिया है। 2019 में संसद में जीतने वाले लगभग एक तिहाई सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे; 40% का कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड था।
सूचना वातावरण	भारत में मुख्यधारा और जन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ भाजपा का समर्थक माना जाता है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है। नफ़रत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार भी व्याप्त हैं - जो मतदान प्रक्रिया को ख़राब कर रहे हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, देश में नफरत फैलाने वाले भाषण कानूनों की अनुपस्थिति कड़ी कार्रवाई को रोकती है। लेकिन सबूत बताते हैं कि घृणित अभियानों के आरोपी सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं को अक्सर छूट मिल जाती है।
भारतका चुनाव आयोग	भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम सौंपा गया है, जिसके पास संविधान (अनुच्छेद 324) और कानून द्वारा संरक्षित विशाल शक्तियां हैं। अदालतों ने भी चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के हाथों को और मजबूत करने का फैसला सुनाया है। लेकिन चुनाव आयोग पर अक्सर अपने कार्य में विफल रहने का आरोप लगाया गया है - जिसमें आदर्श आचार संहिता को लागू करने में निरंतरता की कमी भी शामिल है; सत्तारूढ़ दल के साथ अनुकूल व्यवहार करना; और अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है। समस्या का एक हिस्सा नियुक्तियों पर कार्यपालिका के नियंत्रण को देखते हुए, ईसीआई की स्वतंत्रता की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया है। हाल ही में सरकार ने ईसीआई को स्वतंत्र बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर इस नियंत्रण को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
निवारण का अभाव	नागरिक समाज और विपक्षी राजनीतिक दलों के ईसीआई से उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण की मांग करने और प्राप्त करने के प्रयास असफल रहे हैं। अदालतों का भी सहारा लेने पर भी कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये कारक, फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली के प्रभाव के साथ, सत्तारूढ़ दल को चुनावी स्थान पर सफलतापूर्वक एकाधिकार करने में योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का लक्ष्य कमजोर हो रहा है।

पैनल की रिपोर्ट :

निम्नलिखित पृष्ठों में, हम हाल के चुनावों, 2019 के आम चुनावों के साथ-साथ पिछले वर्षों में राज्य विधानसभा चुनावों के अनुभव के आधार पर, माध्यमिक स्रोतों - प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और वास्तविक चुनावों की चुनौतियों का आकलन प्रदान करते हैं। , ज्यादातर चुनाव पर नागरिक आयोग और अन्य नागरिक समाज समूहों के साथ-साथ मीडिया रिपोर्ट और चुनिंदा प्रकाशित कार्य। यह मूल्यांकन चुनाव प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता के बारे में घरेलू चुनाव निगरानी समूहों, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और मीडिया द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं को बताता है। इसका उद्देश्य जीई 2024 की औपचारिक अधिसूचना के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 2024 के चुनावों की आईपीएमआईई की निगरानी के लिए जमीन तैयार करना है। यह समीक्षा वैचारिक ढांचे, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मानकों का उपयोग करती है, जैसा कि संलग्न बेंचमार्क नोट में निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट।

हम पहले (अध्याय 2 में) जांच करते हैं कि क्या मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और प्रमुख संधि उपकरणों के साथ-साथ भारतीय संविधान में सार्वभौमिक और समान मताधिकार की गारंटी सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है, और प्रमुख मुद्दे क्या हैं . इंच। 3, फिर हम 'वास्तविक विकल्प' के वादे की समीक्षा करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत में अभी भी राजनीतिक बहुलवाद है, साथ ही मतदान प्रक्रिया की मजबूती भी

शामिल है, जो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों के बीच चयन करने की अनुमति देती है। क्या मतदाता 'सूचित विकल्प' चुनने में सक्षम हैं, यह हमारे मूल्यांकन का अगला खंड है (अध्याय 4), मीडिया पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की जांच करना, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या मीडिया सभी दलों को समान कवरेज देता है और गलत/दुष्प्रचार की क्या समस्याएं हैं, साथ ही मतदाताओं को प्रमुख मुद्दों से भटकाने, वोट हासिल करने और समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं की व्यापक अपील की जा रही है। अंतिम खंड (अध्याय 5) भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के संचालन, वहां की प्रमुख चिंताओं, साथ ही उपचार के प्रावधान पर है, जब राजनीतिक दलों के साथ-साथ नागरिक समाज और नागरिकों ने अपनी शिकायतों के निवारण की मांग की है। इसके बाद एक निष्कर्ष अध्याय (6) है, जिसमें कुछ अंतिम विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अध्याय 7 में हम आम चुनाव 2024 की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के साथ-साथ राजनीतिक दलों सहित अधिकारियों के लिए कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त करते हैं, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहाल करना और सभी के लिए समान रूप से सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी देना शामिल है।

2. क्या भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है?

2.1 परिचय

सार्वभौमिक मताधिकार यह सिद्धांत है कि मतदाताओं के व्यापक उचित समूह को बिना किसी भेदभाव के वोट देने के अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए। समान मताधिकार वह विचार है जिसे आमतौर पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' के रूप में व्यक्त किया जाता है।

इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित अधिकारों पर लागू होने वाली कोई भी शर्तें 'उद्देश्य' और 'उचित' मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। जबकि मतदान के अधिकार पर आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है - और सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार के लिए इससे भी अधिक आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है - संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए अनुचित प्रतिबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ, अत्यधिक निवास आवश्यकताओं के साथ-साथ आर्थिक, भाषाई, शामिल हैं। शैक्षिक और साक्षरता आवश्यकताएँ। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है कि सभी पात्र व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें, जिसमें मतदाताओं के पंजीकरण में बाधाओं को दूर करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना भी शामिल है। परिसीमन, चुनावी सीमाओं का रेखांकन, मतदाताओं के वितरण को विकृत नहीं करना चाहिए, किसी भी समूह के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अन्य बातों के साथ-साथ, उपलब्ध जनगणना डेटा, क्षेत्रीय अखंडता, भौगोलिक वितरण और स्थलाकृति सहित कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

हालाँकि, भारत में विशेषज्ञों ने मतदाता सूची से आबादी के कई कमजोर वर्गों, विशेष रूप से मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के साथ-साथ प्रवासी मतदाताओं और बेघरों जैसे समूहों के व्यवस्थित बहिष्कार पर ध्यान दिया है। पिछले कई वर्षों में जम्मू-कश्मीर (J&K) के लोगों को मतदान के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। असम में बंगाली भाषी व्यक्ति, जिन्हें डी-वोटर (संदिग्ध मतदाता) के रूप में पहचाना जाता है, उन्हें भी अपने अधिकार खोने का खतरा है। पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले जम्मू-कश्मीर और असम में भी हाल ही में परिसीमन की कवायद देखी गई है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश हो सकती है।

2.2 वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध

A मतदाता सूची और कमजोर वर्गों का बहिष्कार

चुनाव पर नागरिक आयोग (सीसीई) ने नोट किया है कि भारत के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा दो कारणों में से एक के कारण वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ है: (i) उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं, या (ii) उनकी भौगोलिक स्थिति या अन्य कमज़ोरियाँ उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकती हैं। भारत में, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य वंचित समुदायों के पात्र मतदाता विशेष रूप से मतदाता सूची से बाहर किए जाने के प्रति संवेदनशील रहे हैं। 2019 में, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट पॉलिसी (सीआरडीडीपी) ने अनुमान लगाया कि देश भर में 30 मिलियन से अधिक मुस्लिम मतदाता और 40 मिलियन दलित मतदाता मतदाता सूची से गायब थे।

इस तरह के झूठे बहिष्करण की रिपोर्टें हाल के वर्षों में भी जारी रही हैं। फरवरी, 2023 में, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले, स्थानीय कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक आस्था के नेताओं और विपक्षी राजनेताओं ने आरोप लगाया कि कई जिलों में हजारों मुस्लिम, ईसाई और दलित मतदाताओं को मनमाने ढंग से नामावली से हटा दिया गया। इसके अलावा फरवरी, 2023 में, एक समाचार रिपोर्ट से पता चला कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के कारण अकेले कर्नाटक के शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में हजारों पात्र मतदाता, विशेष रूप से मुस्लिम और दलित, इस तरह के झूठे बहिष्कार के जोखिम में थे।

सीसीई द्वारा पहचाने गए मतदाताओं की अन्य श्रेणियां, जो विशेष रूप से चुनावी प्रक्रिया से बाहर किए जाने के प्रति संवेदनशील हैं, उनमें शामिल हैं:

- भारत के 100 मिलियन से अधिक सर्कुलर मतदाता, जिन्हें वर्तमान नियमों के तहत डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट भेजने की अनुमति नहीं है।
- शहरी बेघर व्यक्ति, प्रत्येक बड़े भारतीय शहर की आबादी का लगभग 1% अनुमानित हैं, जिन्हें मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हासिल करने में कठिनाई होती है।
- ट्रांसजेंडर लोग, जो सामाजिक कलंक का सामना करते हैं और मतदाता पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों को हासिल करने में कठिनाई का सामना करते हैं।
- महिलाएं, जिनमें से 97.2% वोट देने की हकदार हैं, लेकिन केवल 92.7% ही पंजीकृत मतदाता हैं, एकल महिलाओं को विशेष रूप से बहिष्करण का खतरा है।
- यौनकर्मी, जो सामाजिक कलंक का सामना करते हैं और मतदाता पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हासिल करने में कठिनाई का सामना करते हैं।
- हाथ से मैला ढोने वाले, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक कलंकित जाति समूहों से संबंधित हैं।
- कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्य, जिन्हें विकास परियोजनाओं के कारण जबरन विस्थापन और प्रवासन का सामना करना पड़ा है।
- दिव्यांग व्यक्ति, जो राजनीतिक एजेंडे और विकास रणनीतियों में अदृश्य हैं, और अक्सर मतदान प्रक्रिया में भौतिक पहुंच प्रदान किए जाने के बावजूद उदासीन चुनाव कर्मचारियों का सामना करते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के पास पारिवारिक या संस्थागत समर्थन की कमी है।

इस प्रणालीगत बहिष्कार में सहायक के रूप में सीसीई द्वारा पहचाने गए प्रमुख कारकों में मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश, भ्रष्टाचार और चुनाव अधिकारियों के बीच भेदभाव की रूढ़ियों और प्रणालियों को अपनाना शामिल है।

B अन्य माध्यमों से मतदाता सूची से बहिष्करण

सीसीई ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नामों की अनुपस्थिति/दोहराव की आवर्ती समस्या पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि इस तरह का बहिष्करण और गलत समावेशन उस देश में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जहां चुनाव अक्सर बहुत कम अंतर पर जीते और हारे जाते हैं।

सीसीई द्वारा पहचाना गया एक अन्य प्रमुख मुद्दा चुनाव पंजीकरण उद्देश्यों के लिए भारत के आधार डेटाबेस का उपयोग है, यह देखते हुए कि इसने, कई अवसरों पर, बिना आधार वाले या जिनके आधार की जानकारी नहीं थी, उन्हें वैध मतदाताओं के बहिष्करण का मार्ग प्रशस्त किया है। भूत या डुप्लिकेट के रूप में मिलान करें। अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, लगभग 5.5 मिलियन मतदाताओं को आधार के साथ उनके मतदाता पहचान पत्र के दोषपूर्ण लिंक के कारण 2019 में चुनावी प्रक्रिया से बाहर किए जाने की सूचना मिली थी। सीसीई विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने से मतदाताओं को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने और अन्य प्रकार की हेराफेरी का रास्ता खुल सकता है।

B असम में मतदान के अधिकार से इनकार

उत्तर-पूर्वी राज्य असम, ऐतिहासिक रूप से, प्रमुख असमिया-भाषियों और अल्पसंख्यक बंगाली-भाषी व्यक्तियों के बीच तनाव का स्थल रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में भाजपा के उदय के बारे में बताया गया है कि इसने "प्रवासी-विरोधी" आंदोलन में और अधिक स्पष्ट सांप्रदायिक रंग जोड़ दिया है, जैसा कि एक कानूनी विद्वान ने इसके 'व्यापक जातीय-राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट' के रूप में वर्णित किया है। पूरे भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना।'

दशकों से असम में कथित 'अवैध प्रवासियों' को लक्षित करने और दंडित करने के राज्य के नेतृत्व वाले प्रयासों में शामिल हैं: 1990 के दशक में ईसीआई द्वारा 230,000 से अधिक 'संदिग्ध मतदाताओं' का बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होना, साथ ही अर्ध-न्यायिक विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) जिसने, 1985 और मार्च 2019 के बीच, 117,000 से अधिक असम निवासियों को विदेशी घोषित कर दिया है, जिससे उन्हें वोट देने के अधिकार सहित नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

अगस्त 2019 में, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रकाशित किया गया था, जो 'वास्तविक' भारतीय नागरिकों की पहचान करने और 'अवैध प्रवासियों' को बाहर करने के लिए एक बहु-वर्षीय प्रशासनिक अभ्यास की परिणति के रूप में था। जबकि 33 मिलियन से अधिक लोगों ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, कुल 1,906,657 असम निवासियों - राज्य की आबादी का लगभग 6% - को बाहर रखा गया था। लेखन के समय, इन निवासियों की स्थिति कानूनी अधर में बनी हुई है।

हालांकि ईसीआई ने एनआरसी-बहिष्कृत लोगों को असम में बाद के विधानसभा चुनावों में मतदान करने से नहीं रोका है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 2024 के संसदीय चुनावों से पहले कितने लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम पाया है। एनआरसी-बहिष्कृत लोगों के अलावा, फरवरी, 2024 तक लगभग 100,000 ईसीआई-घोषित 'संदिग्ध मतदाता' अभी भी असम में रह रहे हैं, जो मतदान नहीं कर पाएंगे।

2.3 जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को नकारना

मतदाता सूची से बाहर करने के अलावा, जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम-बहुल क्षेत्र के निवासियों को लोकतंत्र से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। जून 2018 में पूर्व भाजपा-सहयोगी राज्य के मुख्यमंत्री (सीएम) के इस्तीफे के बाद से, जम्मू-कश्मीर में किसी भी प्रकार की लोकप्रिय सरकार नहीं है, अब लगभग छह साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के तहत राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की 16 महीने की लंबी अवधि लागू हुई। अक्टूबर, 2019 से, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (एलजी) के नियंत्रण में है।

जबकि अप्रैल-मई, 2019 में जम्मू-कश्मीर में संसद के चुनाव हुए थे, केंद्र सरकार ने अगस्त, 2019 में, पूर्ववर्ती राज्य की नाममात्र स्वायत्तता को एकतरफा रद्द कर दिया था, और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) - जम्मू और कश्मीर में विभाजित और डाउनग्रेड कर दिया था। लद्दाख. निरसन के साथ, केंद्रीय अधिकारियों ने, तत्कालीन राज्य के मुस्लिम-बहुल कश्मीर हिस्से से 2019 में संसद के लिए चुने गए सभी तीन सांसदों सहित, जम्मू-कश्मीर में पूरे राजनीतिक नेतृत्व को लंबे समय तक हिरासत में रखा। भारत तब से राज्य विधानसभा के साथ-साथ ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में विफल रहा है। केंद्र सरकार ने 2020 में, जिला विकास परिषद बनाने के लिए नियमों को संशोधित किया - जिसके लिए नवंबर 2020 में चुनाव हुए - अधिकांश पर्यवेक्षकों द्वारा राज्य-स्तरीय नेताओं के अधिकार को कम करने के केंद्र के प्रयास के रूप में देखा गया। स्थानीय नेताओं ने इसे एक संकेत के रूप में देखा कि यूटी विधानसभा के चुनाव जल्द नहीं होंगे, एक डर की पुष्टि हो गई है।

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की बहाली की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन किया है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा चुनाव कराने में ईसीआई की विफलता एक 'समझौता' संस्था बनने का संकेत है जो 'संवैधानिक आवश्यकताओं के बजाय भाजपा के विचारों को ध्यान में रखती है।'
दिसंबर, 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने - पूर्ववर्ती राज्य की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए - चुनाव आयोग को सितंबर, 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने का आदेश दिया। संभव'। हालाँकि यह ज्ञात नहीं है कि केंद्र सरकार अंततः उस आदेश का अनुपालन करेगी या नहीं, यह भी ज्ञात नहीं है कि अदालत ने तुरंत चुनाव का आदेश क्यों नहीं दिया।

2.4 प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए चुनावी सीमाएँ खींचना

भारत में, विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद 2011 में किया जाता है। जबकि

परिसीमन को राष्ट्रीय स्तर पर 2026 तक रोक दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल ही में असम और जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप गैरमांडरिंग के आरोप लगे हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, असम में बड़ी मुस्लिम आबादी है।

A असम में परिसीमन, संभावित रूप से मुसलमानों और एसटी को अशक्त कर रहा है

असम में, 'अवैध प्रवासियों' की उपस्थिति और 'बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति' को परिसीमन में देरी के कारणों के रूप में उद्धृत किया गया था, जो मूल रूप से 2006 में हुआ था। हालांकि, 2019 में एनआरसी के प्रकाशन ने ईसीआई के लिए मार्ग प्रशस्त किया अभ्यास फिर से शुरू करें. विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन का अंतिम आदेश अगस्त, 2023 में जारी किया गया था, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 126 और संसदीय सीटों की संख्या 14 बरकरार रखी गई थी।

जबकि भाजपा ने स्वदेशी असमिया भाषी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के रूप में नवीनतम परिसीमन की प्रशंसा की है, राजनीतिक विश्लेषकों ने विसंगतियों पर प्रकाश डाला है कि वे चेतावनी देते हैं कि इससे कई समूहों, विशेष रूप से मुस्लिमों के अशक्तीकरण का कारण बन सकता है।

उदाहरण के लिए, कई पहले से अनारक्षित सीटें - जैसे बारपेटा और सिलचर - जहां मुस्लिम मतदाता अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते थे, अब एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। डोटोमा, एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाला एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र, कथित तौर पर एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। एक विश्लेषक का अनुमान है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे उनकी संख्या अब 30 से घटकर लगभग 24 हो जाएगी। एक अन्य विश्लेषक ने बताया कि कुछ सीटों - जैसे डिमोरा, नाओबोइचा, हाजो और बिहाली - का आरक्षण जिन क्षेत्रों में या तो बहुमत है या विभिन्न अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की पर्याप्त आबादी है, वहां एससी उनके मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

B जम्मू-कश्मीर में परिसीमन, संभावित रूप से मुसलमानों को कमजोर कर रहा है

जम्मू-कश्मीर में, परिसीमन का नवीनतम दौर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की देखरेख में मई 2022 में संपन्न हुआ था। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कुल पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, साथ ही सात नए अधिसूचित विधानसभा क्षेत्र बने रहेंगे, जिससे जम्मू क्षेत्र में कुल संख्या 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 हो जाएगी। जम्मू क्षेत्र में छह और कश्मीर में तीन सहित नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

बताया गया कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र को 'तत्काल लोकतंत्र' देने के लिए आवश्यक नवीनतम परिसीमन अभ्यास का बचाव किया था। हालाँकि, भाजपा को छोड़कर, क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभ्यास की निंदा की है, और आरोप लगाया है कि इसके परिणाम मुस्लिम-बहुल कश्मीर में मतदाताओं को कमजोर कर देंगे।

राजनीतिक नेताओं और विश्लेषकों ने बताया है कि सात नव अधिसूचित विधानसभा क्षेत्रों में से छह जम्मू में हैं, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। छह में से चार कथित तौर पर हिंदू-बहुल जिले हैं। परिणामस्वरूप, जम्मू में रहने वाली राज्य की 44% आबादी, 48% विधानसभा सीटों पर मतदान करेगी, जबकि कश्मीर में रहने वाली 56%

आबादी, शेष 52% सीटों पर मतदान करेगी। एक कश्मीरी राजनीतिक नेता ने कहा कि पिछले छह दशकों में, जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या में 13 की वृद्धि हुई है, जबकि कश्मीर में केवल 4 की वृद्धि हुई है।

आलोचकों ने यह भी बताया है कि परिसीमन आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करते समय भूगोल और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कारकों को नजरअंदाज कर दिया है - उदाहरण के लिए अनंतनाग जिले (कश्मीर में) के विधानसभा क्षेत्रों को पुंछ और राजौरी जिलों के साथ विलय कर दिया गया है, जो उनका कहना है कि आगे बढ़ेगा 'कश्मीरी मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से अशक्त किया जा रहा है।

3. क्या भारतीय मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प हैं?

3.1 परिचय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार, चुनावों को 'वास्तविक' माना जा सकता है या नहीं, यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे कुछ प्रक्रियात्मक गारंटी को पूरा करते हैं, और क्या वे मतदाताओं की स्वतंत्र इच्छा को प्रतिबिंबित और प्रभावी करते हैं।

भारत की वर्तमान चुनावी और राजनीतिक प्रणाली की कई विशेषताएं - जिनमें राजनीतिक बहुलवाद को प्रभावित करने वाले मुद्दे शामिल हैं, जैसे राजनीतिक वित्तपोषण की अपारदर्शिता और विपक्षी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का उत्पीड़न, साथ ही मतदान प्रणाली और संचालन में विवादास्पद तत्व, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग वोटिंग मशीनें (ईवीएम) - इस बारे में गंभीर सवाल उठाती हैं कि क्या भारत के चुनाव वास्तव में अपने मतदाताओं को 'वास्तविक विकल्प' प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ चिंताओं को इस खंड में संक्षेप में उजागर किया गया है।

3.2 राजनीतिक बहुलवाद को नकारना? चुनावी बांड और मजबूत रणनीति

ए राजनीतिक बहुलवाद की तुलना में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहुलवाद की संस्कृति को बढ़ावा देने, वास्तविक बहुलवादी राजनीतिक बहस सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रियाओं से विपक्षी उम्मीदवारों को बाहर करने से बचने के लिए बाध्य है। राजनीतिक बहुलवाद के लिए आवश्यक है कि सभी पार्टियाँ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है, और राजनीतिक अभियानों के निष्पक्ष और पारदर्शी वित्तपोषण के लिए चुनावी कानून की आवश्यकता है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए या उनकी उम्मीदवारी या राजनीतिक संबद्धता के कारण किसी भी भेदभाव या नुकसान का सामना नहीं करना चाहिए।

बी। राजनीतिक वित्तपोषण में अपारदर्शिता, विपक्षी दलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है

कई विशेषज्ञों ने नोट किया है कि भारत के मौजूदा राजनीतिक वित्तपोषण परिदृश्य में पारदर्शिता की कमी, राजनीति में प्रवेश बाधाएं बढ़ाना, ईमानदार उम्मीदवारों और पार्टियों को बाहर करना और भ्रष्टाचार के साथ-साथ संदिग्ध कॉर्पोरेट अभिनेताओं के प्रभाव को बढ़ावा देना शामिल है। वर्तमान प्रणाली में जिन प्रमुख कमजोरियों पर विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला है, उनमें अन्य शामिल हैं:

● चुनाव के दौरान राजनीतिक दल कितना खर्च कर सकते हैं, इस पर आधिकारिक सीमा का अभाव, व्यक्तिगत उम्मीदवार कितना खर्च कर सकते हैं, इसकी सीमा मौजूद होने के बावजूद। कथित तौर पर इससे बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को लगभग असीमित खर्च करने में मदद मिली है।
● आयकर (आईटी) अधिनियम में प्रावधान जो राजनीतिक दलों को ₹ 2,000 से कम राशि के दान के स्रोतों का खुलासा करने से छूट देते हैं (2017 तक सीमा ₹ 20,000 थी)। कथित तौर पर इस प्रावधान को बड़े दानदाताओं द्वारा नियमित रूप से दरकिनार कर दिया जाता है जो अपने दान को छोटी-छोटी राशि के कई दान में 'विभाजित' कर देते हैं।

● राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले का पालन करने से इनकार करना, जिसने उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जांच के अधीन 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नामित किया था।
यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था, और ईसीआई और भारत के केंद्रीय बैंक की आपत्तियों के बावजूद, और उचित संसदीय जांच के बिना, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2017 में राजनीतिक वित्तपोषण के एक नए साधन के रूप में चुनावी बांड पेश किया।

पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम में 'काले' धन की भूमिका को कम करने के लिए एक नवाचार के रूप में प्रचारित, राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा जारी किए गए इन गुमनाम वचन नोटों को किसी भी भारतीय व्यक्ति, संघ या निगम द्वारा खरीदा जा सकता है। खरीदी गई रकम और किसी राजनीतिक दल के बैंक खातों में जमा की गई राशि पर कोई सीमा। (खोजी पत्रकारों ने बाद में खुलासा किया कि इन स्पष्ट रूप से गुमनाम बांडों में वास्तव में छिपे हुए अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होते हैं जो संभावित रूप से राज्य को दाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संबंधों की निगरानी करने की अनुमति देते हैं।)

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसके साथ ही कॉर्पोरेट दान पर लगी सीमा को भी हटा दिया, जो पहले पिछले तीन वर्षों में किसी कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 7.5% निर्धारित की गई थी, और पिछली आवश्यकता को हटा दिया गया था कि निगम अपने बयानों में अपने राजनीतिक दान की पूरी सूची शामिल करते थे। खातों का. चुनावी बांड पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद, और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भाजपा और कांग्रेस दोनों को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), भारतीय संघों के विदेशी फंडिंग को विनियमित करने वाले कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, भाजपा सरकार ने भी पूर्वव्यापी संशोधन किया। एफसीआरए, चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों की गुमनाम विदेशी फंडिंग को प्रभावी ढंग से सक्षम बनाता है।
भ्रष्टाचार को वैध बनाने और भारत के अव्यवस्थित राजनीतिक फंडिंग परिदृश्य को और अधिक अस्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा चुनावी बांड योजना की चौतरफा आलोचना की गई थी। भाजपा प्रमुख लाभार्थी थी: लोकतंत्र पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2017 और 2023 के बीच चुनावी बांड के माध्यम से सभी

राजनीतिक दलों द्वारा कुल ₹ 120.1 बिलियन (लगभग 1.45 बिलियन डॉलर) जुटाए गए थे। इसमें से बीजेपी को आधे से ज्यादा (55%) यानी 65.7 अरब रुपये (करीब 800 मिलियन डॉलर) मिले। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केवल 9.3% वोट मिले। अप्रैल 2022 और मई 2023 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान, भाजपा को लगभग ₹ 13 बिलियन (लगभग 157 बिलियन डॉलर) प्राप्त होने की सूचना मिली थी, जो कि उसी अवधि में प्राप्त कुल धनराशि का लगभग 61% था।

चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से पार्टियों द्वारा जुटाए गए धन के बड़े हिस्से में भी भाजपा का वर्चस्व है, एक फंडिंग मार्ग जो योगदानकर्ताओं और लाभार्थियों पर अधिक पारदर्शी है: पिछले 10 वर्षों में, भाजपा को कथित तौर पर चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से ₹ 18.93 बिलियन (लगभग $ 229 मिलियन) से अधिक प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट, जबकि INC को इसी अवधि में केवल ₹ 2.21 बिलियन (लगभग $ 26 मिलियन) प्राप्त हुए हैं।
फरवरी, 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने सूचना के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बांड को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि उन्होंने राजनीतिक दलों और उनके दाताओं के बीच पारस्परिक संबंधों को सक्षम करने का जोखिम उठाया था। एससीआई के फैसले के एक हफ्ते बाद, एक जांच रिपोर्ट से पता चला कि विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करने वाली कम से कम 30 कॉर्पोरेट फर्मों ने 2018-19 के बीच भाजपा को ₹ 3.34 बिलियन (लगभग $ 40.37 मिलियन) का फंड दान किया 2022-23.

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अब तक भुनाए गए सभी चुनावी बांडों के विवरण का खुलासा करने का भी आदेश दिया। 9 मार्च, 2024 तक, एसबीआई को आदेश का पालन करना बाकी था, इसके बजाय उसने जून 2024 के अंत तक विस्तार का अनुरोध किया - 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त होने के एक महीने बाद।

ऊपर उजागर की गई मौजूदा कमज़ोरियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिससे राजनीतिक फंडिंग का परिदृश्य बड़े राजनीतिक दलों - जिनमें भाजपा सबसे शक्तिशाली है - और कॉर्पोरेट हितों की ओर झुका हुआ है, जिससे भारत में राजनीतिक बहुलवाद की वास्तविक स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
सी। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न

कई अंतरराष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं और अन्य पर्यवेक्षकों ने आगामी संसदीय चुनावों से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा नागरिक समाज समूहों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं को डराने-धमकाने, उत्पीड़न और अपराधीकरण में वृद्धि देखी है।

इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थित रूप से सक्रिय प्रतीत होते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत की मुख्य आपराधिक जांच एजेंसी, और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो वित्तीय अपराधों में विशेषज्ञता रखती है, दोनों ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि

उन्हें विशेष रूप से प्रमुखों को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया है। विपक्षी नेता. हाल के महीनों में जिन विपक्षी नेताओं को इन एजेंसियों द्वारा छापे या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है, उनमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कम से कम तीन विपक्ष शासित राज्यों के लोकप्रिय रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री शामिल हैं। अगस्त, 2021 में, यह पता चला कि राहुल गांधी - प्रमुख विपक्षी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति, जो कथित तौर पर ईडी जांच का भी सामना कर रहे हैं - सहित कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के डिजिटल उपकरण संभावित रूप से खराब थे। इजरायल निर्मित स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके अवैध रूप से समझौता किया गया और निगरानी की गई, जो केवल सरकारी एजेंसियों को बेचा जाता है।

अप्रैल, 2023 में, 14 प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा एससीआई से संपर्क करने की सूचना मिली थी, ताकि उनके खिलाफ 'चयनात्मक और लक्षित' तरीके से तेजी से तैनात की जा रही जांच एजेंसियों से राहत मांगी जा सके। अदालत में पार्टियों द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से जितने भी राजनीतिक नेताओं की सीबीआई या ईडी ने जांच की है, उनमें से 95% से अधिक विपक्षी दलों के हैं। 2014 से पहले 10 वर्षों के दौरान क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए राजनीतिक नेताओं की संख्या के संबंधित आंकड़े कथित तौर पर 60% से कम थे।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की चयनात्मक और लक्षित दंडात्मक कार्रवाई - और एससीआई द्वारा हस्तक्षेप करने से कथित इनकार - से पता चलता है कि भारत यह सुनिश्चित करने के अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व से चूक रहा है कि विपक्षी नेताओं को उनकी राजनीतिक संबद्धताओं के कारण भेदभाव या नुकसान का सामना नहीं करना पड़े, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके मतदाताओं के पास राजनीतिक स्पेक्ट्रम से वास्तविक चुनावी विकल्प हैं।

3.3 मतदान संचालन में समझौता: ईवीएम के खिलाफ मामला

ए. मतदान संचालन के संबंध में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

आईसीसीपीआर और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत मतदान और गिनती प्रक्रिया पर पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी प्रथाओं से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और मतपेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बाध्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि गिनती सभी संबंधित पक्षों द्वारा आधिकारिक अवलोकन के लिए खुली है, और उचित शिकायतों और अपील तंत्रों के साथ-साथ ऑडिट प्रक्रियाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है। विशेष रूप से मतदान प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) जैसे डिजिटल नवाचारों को अपनाने के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यापक और क्रमिक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उनकी तकनीकी, वित्तीय और राजनीतिक व्यवहार्यता पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया है।

बी भारत के मतदान संचालन में कमजोरियाँ

2004 के बाद से, भारत में सभी संसदीय और विधानसभा चुनाव दो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा विकसित ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए हैं। एक दूसरा घटक - वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीन - बाद में पेश किया गया था और अब इसे सभी चुनावों में ईवीएम के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है, जाहिर तौर पर मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए एक साधन प्रदान किया जाता है कि उनके वोट सही तरीके से डाले गए हैं, और सक्षम करने के लिए संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट।

कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि भारत में ईवीएम के उपयोग ने अवैध वोटों को कम करने और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि में योगदान दिया है। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भी इन दावों पर जोर दिया है और ईवीएम-वीवीपीएटी को सभी आलोचनाओं से बचाया है। हालाँकि, कई विद्वानों और विशेषज्ञों ने मौजूदा प्रणाली में स्पष्ट कमजोरियों को उजागर किया है, जिन पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, तो समग्र चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास पर असर पड़ने की संभावना है।

चुनाव पर नागरिक आयोग (सीसीई) ने जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भारत की ईवीएम-वीवीपीएटी प्रणाली का विस्तार से विश्लेषण किया, जिसने 2009 में उस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीसीई और अन्य द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख चिंताएं ईवीएम से जुड़ी समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञों में शामिल हैं:

● ईवीएम में दूरस्थ और भौतिक छेड़छाड़ की संभावना: ईसीआई ने दावा किया है कि बाहरी तत्वों के लिए ईवीएम-वीवीपीएटी के साथ दूर से छेड़छाड़ करना असंभव है, यह रेखांकित करते हुए कि वे एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप्स वाली स्टैंड-अलोन मशीनें हैं, और वे असंबद्ध हैं। इंटरनेट या ब्लूटूथ. हालाँकि, CCE के विशेषज्ञों ने बताया है कि दुनिया भर में पहले से ही ईवीएम को हैक किए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें भारतीय ईवीएम का पुराना संस्करण भी शामिल है। सीसीई ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि ईवीएम के डिजाइन में विद्युत चुम्बकीय और अन्य चैनलों के माध्यम से साइड-चैनल हमलों की संभावना पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। सीसीई विशेषज्ञों ने आगे चेतावनी दी कि आधुनिक डेटा एनालिटिक्स - जिसमें भारत की सत्तारूढ़ पार्टी कथित तौर पर महारत हासिल कर रही है - संभावित रूप से केवल कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम को लक्षित करके एक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणामों को बदलने में सक्षम कर सकती है।

कथित तौर पर ईवीएम में भौतिक छेड़छाड़ की संभावना को ईसीआई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान प्रोटोकॉल इस जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त हैं फिर भी, ऐसे कई हालिया उदाहरण सामने आए हैं जो गंभीर संदेह पैदा करते हैं। 2022 में, राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रमुख विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि लगभग 20 ईवीएम भौतिक रूप से 'चोरी' हो गईं, वोटों की आधिकारिक तौर पर गिनती होने से दो दिन पहले। इससे पहले, 2019 में, सूचना का अधिकार

(आरटीआई) कार्यकर्ताओं द्वारा आधिकारिक ईसीआई डेटा के विश्लेषण से कथित तौर पर पता चला था कि निर्माण के बाद लगभग 2 मिलियन ईवीएम 'गायब' हो गए थे। और 2018 में, ईसीआई के अनुसार, ईवीएम-वीवीपीएटी की कथित खराबी - जाहिर तौर पर अत्यधिक गर्मी के कारण - के कारण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड के दर्जनों मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने पड़े। सीसीई ने ईवीएम की कस्टडी श्रृंखला में भी कई प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया है।

ईसीआई इन आलोचनाओं के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में विफल रहा है। सीसीई की मांग कि ईवीएम का डिज़ाइन और प्रोटोटाइप सार्वजनिक ऑडिट के लिए उपलब्ध कराया जाए, आज तक ईसीआई द्वारा अनसुना कर दिया गया है। सितंबर 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) ने भी ईवीएम के स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

● वीवीपैट के साथ ईवीएम का अपर्याप्त क्रॉस-सत्यापन: वीवीपैट की मैनुअल स्लिप टैली के साथ ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का सत्यापन भारत में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। वर्तमान में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के आदेश पर, प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल पांच ईवीएम को वीवीपैट से क्रॉस-चेक किया जाता है। क्रॉस-सत्यापन के लिए ईसीआई का अपना निर्धारित नमूना आकार मूल रूप से प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ईवीएम था। सीसीई के सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि एससी की बढ़ी हुई क्रॉस-चेकिंग दर के साथ भी, मौजूदा प्रणाली कुल मामलों में से लगभग 50% में दोषपूर्ण ईवीएम का पता लगाने में विफल रहेगी।

पेपर ट्रेल्स को ईवीएम के केवल एक छोटे प्रतिशत (प्रति विधानसभा 1) के लिए गिना जाता है। प्रतिशत इस संभावना पर आधारित है कि ईवीएम में तकनीकी त्रुटि हो सकती है। हालाँकि, इस संभावना को पहचानते हुए कि वोटों की रिपोर्ट की गई गिनती में पक्षपात करने के लिए ईवीएम को जानबूझकर दूषित किया जा सकता है, नमूना काफी बड़ा होना चाहिए, और वीवीपैट और ईवीएम के बीच हर विचलन को ट्रैक किया जाना चाहिए और उसका हिसाब देना चाहिए। आज चुनाव आयोग छोटे नमूनों की सांकेतिक गिनती करता है और व्यावहारिक रूप से विचलनों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि ये डाले गए वोटों के अंतर के दायरे के भीतर होते हैं।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभी ईवीएम के कम से कम 50% का क्रॉस-सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज समूहों की मांग, आज तक, ईसीआई और एससी दोनों द्वारा अनसुनी कर दी गई है।

जबकि ईसीआई को पहले बताया गया था कि वह 100% क्रॉस-सत्यापन की मांगों पर सहमत हो गया था, उसने कथित तौर पर सितंबर 2023 में इसकी मांग करने वाली एक याचिका का विरोध किया था, जिसमें ऐसे किसी भी कदम को 'प्रतिगामी विचार' बताया गया था।
●ईवीएम के पीछे की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: 2024 के चुनावों में उपयोग किए जाने वाले भारत के चुने हुए ईवीएम तंत्र की विश्वसनीयता और अखंडता के बारे में दुनिया भर और भारत में कई विशेषज्ञों

द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए, हम इस पर अब भी एक स्वतंत्र पैनल के रूप में बुला रहे हैं। देर से चरण में, इस मामले में उच्चतम स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता वाली तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बुलाई जाएगी, जिसे सभी संबंधितों द्वारा अधिकृत किया जाएगा ताकि मशीनों में ट्रेस करने की अंतर्निहित तकनीकी क्षमता की गारंटी देने के लिए एक असफल-सुरक्षित ऐड-ऑन तरीका विकसित किया जा सके। , आगामी और सभी भविष्य के भारतीय चुनावों में ईवीएम के माध्यम से किए गए सभी वोटों का रिकॉर्ड और अनुवर्ती कार्रवाई। हम यह भी कहते हैं कि उन निर्माताओं और प्रोग्रामरों के नाम, जिन्होंने इन मशीनों को डिज़ाइन किया है, और जो इनका रखरखाव करते हैं, जनता के सदस्यों के लिए पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मशीनों को हैक, तिरछा या पहले से न तो किया जाएगा और न ही किया जा सकता है। इस मामले को सार्वजनिक रूप से ज्ञात किए बिना, एक विशेष राजनीतिक दल के उद्देश्यपूर्ण परिणाम के लिए प्रोग्राम किया गया। इसलिए जनता को सूचित किया जाना चाहिए कि वास्तव में इन ईवीएम मशीनों का मालिक कौन है, किसने इन्हें डिज़ाइन किया है, किसने संभावित हैकिंग के खिलाफ उनका परीक्षण किया है, किसने उन्हें वित्तपोषित किया है, उनके पीछे के अनुसंधान और विकास के लिए भुगतान किसने किया है, और गवर्निंग बोर्ड में कौन बैठता है उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने इनका निर्माण किया है और आगामी 2024 के चुनाव में उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे शब्दों में, हम इन ईवीएम के पीछे की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को पारदर्शी सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बनाने का आह्वान करते हैं क्योंकि उनकी अखंडता (या नहीं) भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल में आघात करती है।

मतदान प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक मशीनरी की विश्वसनीयता और अखंडता, साथ ही वोटों की गिनती और सत्यापन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल, इन सभी का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि कोई चुनाव 'वास्तविक' है या नहीं और इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतदाताओं की इच्छा. ऊपर उजागर की गई चिंताओं के प्रकाश में, और उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने में ईसीआई और एससी की स्पष्ट विफलता के कारण, भारत मतदान संचालन के संबंध में अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से बहुत पीछे रह सकता है।

जनवरी, 2024 में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को भाजपा और 27 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) गठबंधन के बीच पहली चुनावी प्रतियोगिता के रूप में पेश किया गया था। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण रिपब्लिक टीवी है, जिसकी सह-स्थापना एक व्यवसायी और भाजपा समर्थित सांसद ने की थी, जिन्होंने बाद में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी और औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए (और बाद में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नियुक्त किया गया)। अर्नब गोस्वामी, एक समाचार एंकर, जो रिपब्लिक नेटवर्क के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक भी हैं, अक्सर भाजपा के आलोचकों पर हमला करते हैं और कथित तौर पर उन्हें प्रधान मंत्री कार्यालय और अन्य वरिष्ठ भाजपा मंत्रियों तक अपनी पहुंच के बारे में बताते हुए पकड़ा गया है। रिपब्लिक टीवी 2017 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार देश में

सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अंग्रेजी भाषा का समाचार चैनल बना हुआ है। 2022 में, एनडीटीवी, जिसे कई लोग भारत के आखिरी प्रमुख स्वतंत्र टीवी प्रसारक के रूप में देखते हैं, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के अधीन था, जो एक व्यवसायी है जो पीएम मोदी के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है। आरएसएफ ने एनडीटीवी के अधिग्रहण को 'भारत के अग्रणी मीडिया में बहुलवाद का अंत' बताया।

स्वामित्व के अलावा, 2019 में ऑक्सफैम के एक अध्ययन से पता चला कि भारतीय समाचार कक्षों में प्रबंधकीय और संपादकीय पदों पर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बहुत कम से न के बराबर है। यह विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी टेलीविजन समाचारों में तीव्र पाया गया, जहां 'उच्च जाति' के हिंदू ऐसे पदों पर क्रमशः 100% और 89% थे।
विशेषज्ञों ने भाजपा के पक्ष में खुली पक्षपात की इस प्रणाली को बनाए रखने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों पर भी प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि निजी स्वामित्व वाले संगठनों के विज्ञापन और प्रायोजन में गिरावट के साथ, विशेष रूप से सीओवीआईडी -19 महामारी के बाद, विज्ञापन समर्थन पर मीडिया आउटलेट की निर्भरता कम हो गई है। सरकार अनुपातिक रूप से बढ़ी है।

एक गैर-लाभकारी समाचार संगठन द्वारा 2018 में एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि 23 प्रमुख मीडिया संगठनों के वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया अधिकारी, 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत लेने और सामग्री का प्रचार करने के लिए तैयार थे कि भाजपा बनी रहे। सत्ता में, भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने और अल्पसंख्यक विरोधी भड़काऊ और विभाजनकारी सामग्री प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की।
अन्य अध्ययनों ने पुष्टि की है कि जो भारतीय अधिक समाचार मीडिया का उपभोग करते हैं, उनके भाजपा को वोट देने की संभावना काफी अधिक है।

सी. सोशल मीडिया नेटवर्क पर भाजपा समर्थक अभिनेताओं का प्रभुत्व

टेलीविजन समाचारों के उदय के समानांतर, भारत में इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच में भी तेज वृद्धि देखी गई है। फेसबुक और एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) जैसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं, जिनके करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ता हैं, वोह भी महत्वपूर्ण चैनल बन गए हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक प्रचार और गलत सूचना फैलाई जाती है।

जबकि सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के पास अब समर्पित सोशल मीडिया संचालन हैं, भाजपा का 'आईटी सेल' सबसे परिष्कृत, अच्छी तरह से वित्त पोषित और संगठित बताया गया है। भाजपा आईटी सेल के पूर्व नेताओं और सदस्यों को यह बताते हुए रिपोर्ट किया गया है कि कैसे यह जानबूझकर दुष्प्रचार का उत्पादन और प्रसार करके सांप्रदायिक आग को भड़काता है। 2015 में, आईटी सेल के

संस्थापकों में से एक ने पार्टी में व्याप्त 'पागलपन' का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। 2018 में, एक डेटा विश्लेषक, जो पहले भाजपा के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करता था, उसने खुलासा किया कि कैसे नकली वीडियो और ग्राफिक्स को सैकड़ों व्हाट्सएप समूहों में भेजे जाने से पहले संपादित और एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे वे उन लोगों द्वारा अधिक व्यापक रूप से फैलाए जाते हैं जो सामग्री पर विश्वास करते हैं।

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस तरह की रणनीति का खुलेआम समर्थन करता नजर आया है। 2019 के राष्ट्रीय चुनावों की अगुवाई में, अमित शाह - तब भाजपा के अध्यक्ष और अब भारत के गृह मंत्री - ने अपने व्हाट्सएप समूहों पर 3 मिलियन से अधिक लोगों की उपस्थिति और 'किसी भी संदेश को फैलाने' की पार्टी की क्षमता का दावा किया था। लोग, चाहे खट्टे हों या मीठे, असली हों या नकली'। 2019 के चुनावों से पहले के महीनों में, एक खोजी पत्रकार ने ऐसे भाजपा-संचालित व्हाट्सएप समूहों पर 60,000 से अधिक संदेशों की सामग्री का विश्लेषण किया, और पाया कि विश्लेषण की गई सामग्री का 36% हिस्सा राजनीतिक प्रचार के लिए था, जबकि मुस्लिम विरोधी भड़काऊ सामग्री के लिए 24% जितना था। जांच से यह भी पता चला कि इन समूहों पर सरकारी आलोचकों के फोन नंबर साझा किए गए थे, सदस्यों को उन्हें कॉल करने और परेशान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

डी प्रसारण और सोशल मीडिया पर राजनीतिक संदेश भेजने का पैटर्न:

भाजपा समर्थक अभिनेताओं द्वारा मुख्यधारा और सोशल मीडिया नेटवर्क पर प्रभुत्व का मतलब यह है कि इन सेवाओं के औसत भारतीय उपयोगकर्ता अब दुष्प्रचार सहित भाजपा समर्थक, विपक्ष विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी सामग्री के दैनिक और सावधानीपूर्वक बनाए गए हमले के अधीन हैं। विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक ही कथा को आगे बढ़ाने वाले अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ। प्रसारण और सोशल मीडिया नेटवर्क पर विपक्षी राजनेताओं और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का चित्रण स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा अत्यधिक नकारात्मक और उत्तेजक पाया गया है।

राजनीतिक संदेशों में जो पैटर्न बने हुए हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को हिंसक, भारत के अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में चित्रित करना, उन्हें विश्वासघाती 'राष्ट्र-विरोधी' और 'देशद्रोही', जनसांख्यिकीय विस्तारवादी, और सशस्त्र चरमपंथी और अलगाववादी समूहों के सदस्य या सहानुभूति रखने वालों के रूप में चित्रित करना शामिल है। विपक्षी राजनेताओं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को न केवल भ्रष्ट, कुलीन और वंशवादी के रूप में चित्रित किया गया है, बल्कि आतंकवादियों और 'देश-विरोधी' के रूप में भी चित्रित किया गया है। 2019 में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) के शोधकर्ताओं ने 'ट्रांस-' पर प्रकाश डाला। इस संदेश की औसत प्रकृति, और इस बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया के बीच घृणा सामग्री की समकालिकता के परिणामस्वरूप एक पारस्परिक रूप से मजबूत तंत्र बन गया है, जहां भारतीय भी, जो सोशल मीडिया पर उनके सामने आने

वाली कुछ घृणित गलत सूचनाओं को सत्यापित करना चाहते हैं, उन्हें इसकी पुष्टि मिल जाएगी। मुख्यधारा मीडिया पर भी ऐसा ही है। इसके विपरीत, मुख्यधारा के मीडिया पर घृणित, सनसनीखेज और रूढ़िवादी सामग्री की प्रबलता का मतलब है कि सोशल मीडिया पर सामग्री पर विश्वास किए जाने और आगे साझा किए जाने की अधिक संभावना है।

4.3 विपक्षी सदस्यों और असहमत लोगों के खिलाफ कार्रवाई

जहां वे जीत नहीं सकते, वहां भाजपा नियंत्रण करना चाहती है। 2024 के चुनावों की अगुवाई में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आलोचनात्मक और स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ों और तथ्य-जांचकर्ताओं की आवाज़ को दबाने और सूचना के मुक्त प्रवाह पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाने के परिणामस्वरूप विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पहले ही गिरकर 161 (180 देशों में से) हो गई है। अगस्त 2023 में, संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया, जो सरकार को फर्मों से जानकारी मांगने और ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, जबकि राज्य एजेंसियों को इसके दायरे से छूट देता है। दिसंबर, 2023 में, सरकार ने एक नया दूरसंचार विधेयक पेश किया, जिसकी अधिक निगरानी को सक्षम करने और व्यापक इंटरनेट शटडाउन को लागू करने के लिए अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई। भारत पहले से ही सबसे अधिक संख्या में इंटरनेट शटडाउन वाले लोकतंत्रों की सूची में शीर्ष पर है, और पिछले पांच वर्षों से लगातार 'दुनिया की इंटरनेट शटडाउन राजधानी' का संदिग्ध खिताब अर्जित कर रहा है। मार्च 2024 तक, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने 2012 के बाद से देश भर में 809 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए हैं, जिनमें से 535 (66%) 2019 के बाद से रिपोर्ट किए गए हैं। 2019 के आम चुनावों के दौरान, कम से कम 3 राज्यों से इंटरनेट शटडाउन की सूचना मिली थी। कथित तौर पर प्रतिशोध के डर के कारण वैश्विक सोशल-मीडिया कंपनियां भी स्वतंत्र संवाद के लिए जगह को मजबूत करने के लिए काम करने के बजाय सरकारी आदेशों का पालन करने लगी हैं। फेसबुक और एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर खतरनाक दुष्प्रचार और उत्तेजना फैलाने वाले भाजपा समर्थक खातों को सेंसर करने या हटाने में नियमित रूप से विफल रहते हैं, जबकि महत्वपूर्ण पत्रकारों और तथ्य-जाँचकर्ताओं के खातों और पोस्ट को हटाने के सरकारी आदेशों का पालन करते हैं।

साथ ही, राजनीतिक दलों द्वारा पहले से ही अपनी आउटरीच गतिविधियों में एआई-संचालित डीपफेक तकनीक का उपयोग करने की सूचना है, जिसमें मृत राजनीतिक नेताओं के दृश्य और ऑडियो का उपयोग करना शामिल है। देश भर में कई निजी विक्रेता कथित तौर पर वॉयस क्लोनिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो राजनीतिक नेतृत्व को ऑन-ग्राउंड पार्टी कार्यकर्ताओं को 'व्यक्तिगत संदेश' देने की अनुमति दे रहे हैं, एक विशेषज्ञ ने आगामी चुनावों के दौरान एआई-सुविधा वाले कंटेंट मार्केटिंग को 60 मिलियन डॉलर के बाजार अवसर के रूप में वर्णित किया है।

4.4 चुनावी रणनीति के रूप में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, घृणास्पद भाषण और दुष्प्रचार

जबकि लगभग सभी भारतीय राजनीतिक दल चुनावी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं और वोट मांगते समय सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं की अपील करते हैं, भाजपा इस प्रवृत्ति में सबसे आगे रही है।
धार्मिक ध्रुवीकरण - और अक्सर, हिंसा - को विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि इसने भाजपा की राष्ट्रीय प्रमुखता में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसने सत्ता कैसे कायम रखी है। भारत में राज्य-स्तरीय चुनावों के शोधकर्ताओं ने पाया है कि भाजपा की चुनावी जीत से निर्वाचन क्षेत्र में जातीय संघर्ष की संभावना 10% बढ़ जाती है, जबकि विपक्ष की जीत के मामले में संभावना 32% कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि 'धार्मिक दंगे' - जो शायद ही कभी स्वतःस्फूर्त होते हैं और आमतौर पर हिंदू लामबंदी के उद्देश्य से 'उत्पन्न' होते हैं - चुनाव से पहले वाले वर्ष में होते हैं, जिससे भाजपा के वोट शेयर में 5-7% की वृद्धि होती है। .
हाल के वर्षों में, भाजपा इस रणनीति को दोगुना करती हुई दिखाई दी है। फरवरी, 2019 में, आम चुनावों से पहले, कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 40 अर्धसैनिक कर्मियों के मारे जाने के बाद, झूठी और घृणित ऑनलाइन सामग्री की बाढ़ के कारण फेसबुक इंडिया की दुष्प्रचार टीम के प्रमुख को सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करनी पड़ी कि उन्होंने 'कभी नहीं देखा था' कुछ भी' पहले जैसा। नौ सप्ताह की आधिकारिक प्रचार अवधि के दौरान, शोधकर्ताओं ने शीर्ष राजनेताओं द्वारा नफरत भरे भाषण के कम से कम 40 उदाहरण दर्ज किए। और दिसंबर, 2019 में, सीएए विरोधी आंदोलन पर भाजपा की प्रतिक्रिया - जो दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव अभियान के साथ मेल खाती थी, और फरवरी 2020 में मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा में परिणत हुई - प्रदर्शनकारियों और अन्य सरकारी आलोचकों को 'के रूप में ब्रांडिंग' करने पर केंद्रित थी। शहरी नक्सली' और 'देशद्रोही' 'गोली के पात्र.'

तब से, इस तरह के संदेशों का स्वर और भाव और भी अधिक स्पष्ट हो गया है - शक्तिशाली हिंदू धार्मिक नेताओं, जिनमें कुछ भाजपा से करीबी संबंध रखते हैं, ने 'म्यांमार की तरह', मुसलमानों के खिलाफ 'स्वच्छता अभियान' चलाने के लिए खुले तौर पर नरसंहार का आह्वान किया है। और 'उनमें से कम से कम 20 लाख' को मार डालो, और मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो और उन्हें गर्भवती करो। घृणास्पद भाषण ईसाइयों और सिखों के साथ-साथ दलितों पर भी निर्देशित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों और विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के चुप रहने और अपराधियों के लिए दंडमुक्ति के आदर्श बन जाने के कारण हिंसा की ऐसी उत्तेजना हाशिए से मुख्यधारा में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अल्पसंख्यक विरोधी घृणा भाषण के इस विस्तार के बारे में चिंता व्यक्त की है, उनमें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार

उच्चायुक्त, नरसंहार की रोकथाम पर विशेष सलाहकार और एक दर्जन से अधिक विशेष प्रक्रिया जनादेश-धारक शामिल हैं।

इन चेतावनियों के बावजूद, भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण को मुख्य तत्व के रूप में उपयोग करना जारी रखती है। जनवरी, 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवैध रूप से नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक हिंदू मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक विश्लेषकों ने आगामी चुनावों से पहले भाजपा के अभियान की शुरुआत के रूप में देखा। इस समारोह की अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिससे पूरे भारत में कम से कम आठ राज्यों में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क उठी। ईसाइयों और दलितों को भी निशाना बनाया गया. भाजपा ने नफरत भरे भाषण और उकसावे में शामिल राजनीतिक नेताओं को संरक्षण और पुरस्कृत करना भी जारी रखा है - उदाहरण के लिए, नवंबर, 2023 में तेलंगाना में प्रांतीय चुनावों से पहले, भाजपा ने एक विधायक के निलंबन को रद्द कर दिया, जिसे नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए कुछ समय के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। और उन्हें अपने उम्मीदवारों में से एक के रूप में नामित किया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के मतदाता अत्यधिक सांप्रदायिक माहौल में आगामी राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन नफरत भरे भाषण और दुष्प्रचार को विनियमित करने के चुनाव आयोग के प्रयासों को विशेषज्ञों ने कमजोर और अप्रभावी बताया। 2024 में जोखिम काफी अधिक प्रतीत होता है।

5. क्या भारत में चुनावों का संचालन स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण है?

5.1 परिचय

मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व के विस्तार के रूप में, चुनावी प्रबंधन निकाय (ईएमबी) चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। ईएमबी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, निष्पक्ष और आईसीसीपीआर के साथ संगत स्थापित कानूनों के अनुसार आयोजित की जाए। उनका निर्णय लेना खुला, पारदर्शी और अधिकतम परामर्शात्मक होना चाहिए, और सभी हितधारकों को प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी उपाय के अधिकारों के अनुसार, राज्य स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा या अन्य शिकायतों और अपील प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। चुनावी कैलेंडर के संदर्भ में उपाय त्वरित, पर्याप्त, प्रभावी और लागू करने योग्य होने चाहिए।
भारत में, भारतीय चुनाव आयोग - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की देखरेख करने वाली संवैधानिक संस्था - ने ऐतिहासिक रूप से एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का आनंद लिया है। हालाँकि, हाल के वर्षों में उस पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में विफल रहने और भाजपा के प्रति पक्षपाती या अधीन होने का आरोप लगाया गया है।

5.2 भारत निर्वाचन आयोग - चुनाव का मध्यस्थ

ईसीआई को अपना अधिकार भारत के संविधान (अनुच्छेद 374) से प्राप्त होता है, जो संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो भ्रष्ट प्रथाओं और चुनावी को निर्दिष्ट करता है। अपराध करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), दिशानिर्देशों का एक गैर-वैधानिक सेट है जो ईसीआई द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही लागू हो जाता है, जिसका उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता के रूप में कार्य करना है। . एमसीसी के आठ भागों में से प्रमुख भाग VII है, जो सत्ता में पार्टियों को संबोधित करता है, और सरकारी मंत्रियों के अभियान दौरों, सरकारी परिवहन और आवास के उपयोग और सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाओं पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। . ईसीआई के पास एमसीसी का उल्लंघन करने पर पार्टियों और उम्मीदवारों की निंदा करने की शक्ति है। अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक कानूनों को लागू करके एमसीसी के कुछ प्रावधानों को भी लागू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट (एससीआई) ने आगे स्पष्ट किया है कि जब मौजूदा कानून चुनावों के संचालन में किसी स्थिति से निपटने के लिए मौन या अपर्याप्त होते हैं, तो ईसीआई के पास उचित समझे जाने पर कार्य करने की पूर्ण शक्तियां होती हैं, इस प्रकार ईसीआई को अधिक अधिकार मिलते हैं। फिर भी ईसीआई को अपने स्वयं के कानूनों और नियमों और मॉडल कोड को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले के रूप में देखा गया है।

5.3 ईसीआई द्वारा अपने संवैधानिक अधिदेश का निष्पादन

चुनाव पर नागरिक आयोग (सीसीई) ने हाल के वर्षों में विपक्षी राजनीतिक दलों और अन्य नागरिक समाज अभिनेताओं द्वारा ईसीआई के खिलाफ लगाए गए कई आरोपों को उजागर किया है, जिसमें चुनाव के पहले, उसके दौरान और बाद में पक्षपात और पक्षपात का आरोप लगाया गया है। एक। ईसीआई की चुनाव पूर्व कार्यप्रणाली की आलोचना

तारीखों की घोषणा में पक्षपात के आरोप: हाल के वर्षों में कई मौकों पर, ईसीआई पर चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी करने का आरोप लगाया गया है, और इसलिए एमसीसी के प्रभाव में आने के लिए, ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें अंतिम समय में विकास की घोषणा कर सकें। योजनाएं:

- 2017 में गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले, विपक्ष शासित हिमाचल प्रदेश के लिए तारीखों की घोषणा के बावजूद, भाजपा शासित गुजरात के लिए मतदान और गिनती की तारीखों की घोषणा में देरी करने के लिए ईसीआई की आलोचना की गई थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ईसीआई की देरी - और इसके परिणामस्वरूप एमसीसी के प्रभावी होने में देरी - ने राज्य और केंद्र में भाजपा सरकारों को चुनावों से पहले गुजरात-केंद्रित विकास योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा करने की अनुमति दी।

- अक्टूबर 2018 में राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, ईसीआई पर चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी करने और प्रधान मंत्री मोदी को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने में सक्षम बनाने का आरोप लगाया गया था, जहां मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई थी। राज्य के किसान.
- ईसीआई पर 2019 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा में देरी करने और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए कई चुनावी रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में विकास परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन करने और छह अंतिम घोषणा करने का मार्ग प्रशस्त करने का भी आरोप लगाया गया था। संसद में मिनट आपातकालीन अध्यादेश.

मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को संबोधित करने में अवज्ञा:
ईसीआई पर मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आरोपों के जवाब में 'आक्रामक मुद्रा' अपनाने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिए, जब विपक्षी नेताओं ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मतदाता सूचियों में डुप्लिकेट की उपस्थिति का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट (एससीआई) का दरवाजा खटखटाया, तो ईसीआई ने एक नेता पर उसकी छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया था।

बी. ईसीआई द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने की आलोचना

सीसीई विशेषज्ञों ने हाल के वर्षों के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला है कि ईसीआई अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करने और राजनीतिक दलों, विशेष रूप से भाजपा, पर एमसीसी का उल्लंघन करने से रोकने में विफल रही है।
● 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, एमसीसी के संभावित उल्लंघन में, पीएम मोदी के नाम पर एक फ्री-टू-एयर टीवी चैनल और उनकी रैलियों और अन्य प्रचार सामग्री का सीधा प्रसारण पूरे चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित होता रहा। बताया गया कि ईसीआई ने केंद्र सरकार से केवल स्पष्टीकरण मांगा था। मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद तक चैनल लाइव रहा।

● 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, ईसीआई ने निष्कर्ष निकाला कि पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान सैन्य अभियानों और सेना के जवानों के बार-बार आहवान के दौरान एमसीसी का उल्लंघन नहीं किया था। ऐसा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने पहले सभी दलों को चुनाव प्रचार के दौरान सशस्त्र बलों का जिक्र करने से परहेज करने की सलाह दी थी। ईसीआई ने अलग से यह भी निष्कर्ष निकाला कि जब पीएम मोदी ने एंटी-सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण की घोषणा करते हुए टेलीविजन पर संबोधन दिया तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के लिए एमसीसी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया। जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में भारत की सशस्त्र सेनाओं को 'मोदी के सैनिक' कहा, तो ईसीआई ने उन्हें ऐसे बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी।

● जबकि इसने सांप्रदायिक चुनावी भाषणों पर रोक लगाने वाले एमसीसी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने से भाजपा के दो सहित तीन शीर्ष नेताओं को अस्थायी रूप से रोक दिया, ईसीआई ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी, जिन्होंने भी इसी तरह के भाषण दिए थे।

● ईसीआई को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ऑनलाइन प्रचार, राजनीतिक प्रचार और दुष्प्रचार को विनियमित करने में भी 'बुरी तरह विफल' पाया गया, खासकर मतदान से पहले 48 घंटे की 'मौन अवधि' के दौरान जब सभी मीडिया पर चुनावी विज्ञापन वर्जित है। 2019 में 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान, ईसीआई को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक भाजपा पदाधिकारी को अनुबंधित करने की सूचना मिली थी।

शीर्ष भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक चुनावी भाषणों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करने में ईसीआई की विफलता 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भी स्पष्ट हुई थी। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार में तत्कालीन कनिष्ठ मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में बताया गया था कि उन्होंने भीड़ को बुलाया था। 'गद्दारों को गोली मारो' के लिए चुनावी रैली - मुसलमानों और सरकार के आलोचकों के संदर्भ में, जो उस समय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में लगे हुए थे। आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को लागू करने और पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बजाय, ईसीआई ने उन पर केवल अस्थायी प्रचार प्रतिबंध लगाया।

सी चुनाव के बाद ईसीआई की कार्यप्रणाली की आलोचना

ईसीआई को चुनाव अवधि के बाहर पक्षपात में शामिल होने के लिए भी आलोचना झेलनी पड़ी है। उदाहरण के लिए, जनवरी 2018 में, ECI ने दिल्ली विधानसभा से विपक्षी आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की। सितंबर 2019 में, ईसीआई को अयोग्यता की अवधि (चुनाव लड़ने से) को कम करने के लिए और अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा, जो उसने पहले सिक्किम के सीएम पर लगाई थी। दो दिन पहले ही भाजपा ने उसी नेता के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया था।

5.4 चुनावी उपाय और चुनावी न्याय

हाल ही में ईसीआई का सार्वजनिक रुख - और इस रिपोर्ट के पिछले खंडों में उजागर किए गए कई प्रमुख मुद्दों पर सभी हितधारकों के साथ सार्थक जुड़ाव की कमी, इन आरोपों को और अधिक बल देती प्रतीत होती है कि यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रही है। चुनावी उपचार की इन विफलताओं में से कुछ में शामिल हैं:

एक। मतदाता सूची से गलत बहिष्करण: सीसीई विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि ईसीआई मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार पर नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों की प्रतिक्रिया पर शायद ही कभी प्रतिक्रिया देता है या स्वीकार करता है। (अध्याय 4.1 में विस्तृत)

बी। परिसीमन: ईसीआई पर असम में परिसीमन प्रक्रिया की सीधे निगरानी करने का आरोप है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह राजनीति से प्रेरित है और राज्य के कई मुस्लिम निवासियों को मताधिकार से वंचित कर देगा। (अध्याय 4.1 में विस्तृत) बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम परिसीमन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है और कश्मीर में परिसीमन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग की संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा है।

सी। ईवीएम और वीवीपीएटी की एंड-टू-एंड सत्यापनीयता: भारतीय नागरिक समाज संगठन वर्तमान में सभी वोटों की वीवीपैट के साथ 100% क्रॉस-सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग करते हुए मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं। (धारा 4.2 में विस्तृत) इन याचिकाओं में से एक के जवाब में, ईसीआई ने 100% सत्यापन की मांग को एक 'प्रतिगामी विचार' कहा था, और कहा था कि भारतीय मतदाताओं को 'मौलिक' अधिकार नहीं है। उनके वोट को वीवीपैट के माध्यम से सत्यापित किया गया कि उनका वोट डाला गया था और दर्ज के रूप में गिना गया है। ईसीआई ने लगातार इन दावों से ईवीएम का बचाव करना जारी रखा है कि उनमें छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। फरवरी, 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से संबंधित कई मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को 'अतिसंदेहास्पद' होने के लिए दंडित किया था।

डी। चुनावी बांड: जब विवादास्पद चुनावी बांड योजना (धारा 4.2 में विस्तृत) पहली बार 2017 में पेश की गई थी, तो यह बताया गया था कि ईसीआई ने उपकरणों का विरोध किया था, चेतावनी दी थी कि उनका 'राजनीतिक वित्त/वित्त पोषण की पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा' राजनीतिक दल।' 2021 तक, जब नागरिक समाज संगठनों ने विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बांड जारी करने पर रोक लगाने की मांग की, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ईसीआई ने अपना रुख बदल दिया है, याचिका का विरोध किया और रेखांकित किया कि वह चुनावी बांड के विरोध में नहीं है। फरवरी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के कारण चुनावी बांड को रद्द कर दिया।

5.5 भारत का चुनाव आयोग - मध्यस्थ, समझौता?

भारत में चुनावों के संचालन के बारे में राजनीतिक दलों के साथ-साथ नागरिक समाज समूहों द्वारा आलोचना का एक बड़ा हिस्सा चुनाव अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण भूमिका, विपक्ष की कीमत पर सत्ता में राजनीतिक दल का पक्ष लेने को लेकर रहा है। पर्यवेक्षकों ने संविधान द्वारा संरक्षित ईसीआई द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण शक्ति और अधिकार के बावजूद, ईसीआई की स्वतंत्रता की कमी पर इस खराब प्रदर्शन की व्याख्या की है, इस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है।

विशेषज्ञों द्वारा पहचानी गई ईसीआई की शक्तियों और स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख कमजोरियों में शामिल हैं:

● मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एवं अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति एवं निष्कासन की व्यवस्था। दिसंबर 2023 में, संसद ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधान मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री और विपक्ष के नेता के चयन से की जाएगी, जिससे तत्कालीन सरकार को प्रभावी रूप से वीटो मिल जाएगा। इस पर कि चुनाव की निगरानी कौन करेगा. यह कानून सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए।

● चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने वाले पाए जाने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने के अधिकार की कमी।

यह देखना शिक्षाप्रद है कि ईसीआई दुनिया में अन्य जगहों के चुनाव अधिकारियों से कैसे तुलना करता है, खासकर स्वतंत्रता की कसौटी पर। तालिका 2 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के तरीके के प्रमुख कारकों और चुनावी अधिकारियों की स्वतंत्रता के लिए उनके निहितार्थ पर दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्रीय चुनावी निकायों के साथ भारत के चुनाव आयोग की एक त्वरित तुलना प्रदान करती है। भारत अकेला खड़ा है, ईसीआई की व्यवस्था उसके सदस्यों को प्राप्त स्वतंत्रता को सीमित कर रही है।

तालिका 2: चुनाव अधिकारियों की तुलना - उनकी स्वायत्तता

देश	भारत	दक्षिण अफ्रीका	ब्राज़ील
सदस्य	3 सदस्य (मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त)	6 सदस्य (1 अध्यक्ष - संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, 1 मुख्य चुनाव अधिकारी, 4 आयुक्त)	6 सदस्य (3 सर्वोच्च संघीय न्यायालय (एसटीएफ) न्यायाधीश, 2 सुपीरियर न्यायालय (एसटीजे) न्यायाधीश, 2 वकील)
नियुक्ति	कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करती है। चयन समिति जिसमें प्रधान मंत्री	नेशनल असेंबली के बहुमत द्वारा अनुशंसित, एक स्वतंत्र पैनल द्वारा चयनित और एक समिति द्वारा नामांकित, नेशनल	सभी एसटीजे न्यायाधीशों के बीच 3 एसटीजे न्यायाधीश गुप्त रूप से चुने गए, 2 एसटीजे न्यायाधीश सभी एसटीजे

	(प्रमुख), केंद्रीय मंत्री (प्रधान मंत्री द्वारा नामित), लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, राष्ट्रपति को उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं जो उन्हें नियुक्त करते हैं (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023)	असेंबली के आनुपातिक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (चुनाव आयोग अधिनियम 51, 1996, कला 6)	न्यायाधीशों के बीच गुप्त रूप से चुने गए, 6 वकील एसटीएफ द्वारा नामित किए गए जिनमें से 2 को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया (ब्राजील का संविधान, अनुच्छेद 119)
समय अवधि	6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु	7 वर्ष	2 वर्ष
जिम्मेदारिय	पार्टियों को मंजूरी देता है, चुनावों की वैधता तय करता है, पारदर्शिता, चुनाव बुला सकता है, पार्टी के प्रतीक, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।	पार्टियों को मंजूरी देता है, चुनावों की वैधता तय करता है, पारदर्शिता, चुनाव बुला सकता है, पार्टी के प्रतीक, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।	चुनावों की निगरानी और संचालन, मतदाता शिक्षा
स्वतन्त्रता	नियुक्ति स्वतंत्र नहीं है क्योंकि सरकार की आवाज प्रमुख है, मूल रूप से ECI एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय के रूप में था	स्वतंत्र और केवल संविधान और कानून के अधीन	स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण

6 निष्कर्ष

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और भारत के लोकतंत्र का भविष्य

चुनाव तीन अलग-अलग लेकिन अतिव्यापी प्रक्रियाओं के चौराहे पर होते हैं, जिनमें राजनीतिक, तकनीकी और मानवाधिकार संबंधी विचार शामिल होते हैं। वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के मौलिक अधिकार को सुविधाजनक बनाने का एक साधन है। वे एक तंत्र भी हैं जिसके द्वारा सरकार के अधिकार के आधार के रूप में लोगों की इच्छा व्यक्त की जाती है। विविधता और बहुलवाद को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को लोगों की स्वतंत्र रूप से व्यक्त पसंद को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि चुनाव के नतीजे उनकी पसंद को दर्शाते हैं।
[मानवाधिकार और चुनाव मानक - कार्य योजना, दिसंबर 2017, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय; कार्टर सेंटर]

भारत में प्रचलित फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) चुनावी प्रणाली - जहां एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार सीट जीतता है - अपेक्षाकृत सरल होने के बावजूद, यह हमेशा वास्तव में प्रतिनिधि जनादेश की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उम्मीदवार जीत सकता है एक प्रतियोगिता में आधे से भी कम वोट हासिल करने के बावजूद। पर्यवेक्षकों ने देखा है कि कैसे एफपीटीपी ज्यादातर अग्रणी पार्टी की सीटों की हिस्सेदारी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके बहुमत हासिल करती है, जबकि साथ ही यह छोटी पार्टियों को दंडित भी करती है। 2019 में 37.4% वोटों के साथ बीजेपी के पास 56% सीटें थीं। 2014 में 31% पीएफ वोटों के साथ बीजेपी की सीटों में हिस्सेदारी 52% थी। यह व्यवस्था आज सत्ता में प्रमुख पार्टी भाजपा को पुरस्कृत कर रही है। लेकिन चुनावी विकृति ने अतीत में कांग्रेस को भी पुरस्कृत किया है, जब वह प्रमुख पार्टी थी। 1951 और 1971 के बीच, बीस वर्षों तक, कांग्रेस ने कभी भी बहुमत मत हासिल नहीं किया - इस अवधि के दौरान औसत वोट शेयर 45% था - फिर भी उसे लगभग 70% सीटों के साथ और भी बड़ा संसदीय बहुमत प्राप्त हुआ। भाजपा द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ, एफपीटीपी प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए विपक्ष को और अधिक हाशिये पर धकेलने, अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आधार तैयार कर सकती है।

भारत जैसे बड़े देश के लिए, एफपीटीपी को उसकी विविध पहचानों का प्रतिनिधित्व न करने वाला भी माना जाता है, जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुरूप अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में विफल रहता है। 1980 से 2015 तक, जिस समय भाजपा ने अपना पैर जमाया, कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व खो दिया, और जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात 11.1% से बढ़कर 14.2% हो गया, लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या आधे से अधिक (49 से घटकर) रह गई। 25, 534 के घर में)। शोधकर्ता इसके लिए भाजपा को दोषी मानते हैं, जिसने कभी भी कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों से अधिक का समर्थन नहीं किया है। गौरतलब है कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी उच्च मुस्लिम सघनता वाले क्षेत्रों को छोड़कर मुस्लिम उम्मीदवारों को नामांकित करना बंद कर रही हैं। 2019 के चुनाव में सभी दलों ने मिलकर केवल 8.9% मुस्लिम उम्मीदवारों को नामांकित किया। लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों में मुसलमानों की संख्या केवल 4.2% है। भारत में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो कभी बहुत अच्छा नहीं था, तेजी से ख़त्म हो रहा है। आधी आबादी और

मतदाताओं में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भी बदतर है - नामांकित और निर्वाचित लोगों के बीच यह आंकड़ा फिर से निराशाजनक स्तर पर है।

भारतीय चुनाव प्रणाली की इन मूलभूत कमजोरियों के बावजूद, भारत में चुनावी लोकतंत्र के स्वास्थ्य की हमारी समीक्षा से पता चलता है कि वस्तुतः, भारत स्वतंत्र और वास्तविक चुनावों पर कई अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुरूप कानूनी सुरक्षा उपाय हैं जो भारतीय नागरिकों को अपनी राजनीतिक पसंद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। यदि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सहित घरेलू कानून और प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

फिर भी, जैसा कि समीक्षा से पता चलता है, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाली सत्तावादी प्रवृत्ति तेजी से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उस ताने-बाने की जगह ले रही है जिसने 1947 में आजादी के बाद से भारत के धर्मों की विविधता और सांस्कृतिक आधारों को आवाज दी थी। रिपोर्ट में पहले से ही कुछ सत्तावादी प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है जगह में। उदाहरण के लिए, विपक्षी राजनेताओं और संविधान की रक्षा करने वाले नागरिक समाज को सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौजूदा पार्टी के पक्ष में चुनावी बांड के माध्यम से चुनावी फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के वादे का उल्लंघन है। और भारत की मीडिया की स्वतंत्रता इस तरह से तेजी से कम हो गई है कि चुनावी विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है। यदि मतदाता की स्वतंत्र पसंद के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता में और क्षरण होता है, तो भारत एक पूर्ण विकसित बहुसंख्यकवादी और सत्तावादी राज्य में बदल सकता है।
इस प्रवृत्ति की पुष्टि सांख्यिकीय विश्लेषण से होती है। फ्रीडम हाउस और वी-डेम के अनुसार, भारतीय लोकतंत्र की स्थिति को अब केवल 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' माना जाता है, इस हद तक कि इसे 'चुनावी निरंकुशता' के रूप में वर्णित किया जा रहा है - बुनियादी स्वतंत्रता सहित 'मौलिक लोकतंत्र' पर हमलों के कारण और नागरिक स्थान. अन्य ब्रिक्स देशों, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील की तुलना में भारत के प्रमुख चुनावी और लोकतंत्र सूचकांक, (तालिका 3) दिखाते हैं कि भारत कितना पीछे है, और कैसे गिरावट जारी है।

Table 3: Key electoral and democracy indicators, by states
तालिका 3: राज्यों के अनुसार प्रमुख चुनावी और लोकतंत्र संकेतक

Indicators	Year	India	South Africa	Brazil
V-Dem Liberal Democracy Index Rank	2023	104	49	32
	2022	97	51	58
V-Dem Electoral Democracy Index Rank	2023	110	53	36
	2022	108	55	58
V-Dem Clean Elections Index	2023	0.51	0.77	0.84
	2022	0.53	0.72	0.86
V-Dem Electoral Management Body (EMB) Capacity	2023	1.42	1.34	2.99
	2022	1.73	1.34	2.96
V-Dem EMB autonomy	2023	0.98	2.17	3.49
	2022	0.83	2.17	3.45
Electoral Integrity Project Score (2023)		59	69	69
Free and fair elections Bertelsmann Transformation Index (2022)		8 out of 10	9 out of 10	9 out of 10
V-Dem EMB autonomy	2023	0.98	2.17	3.49
	2022	0.83	2.17	3.45
Electoral Integrity Project Score (2023)		59	69	69
Free and fair elections Bertelsmann Transformation Index (2022)		8 out of 10	9 out of 10	9 out of 10

ग्राफ़ 1 दिखाता है कि 2014 के बाद से भारत के वी-डेम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील की तुलना में) में कितनी तेज़ गिरावट आई है।

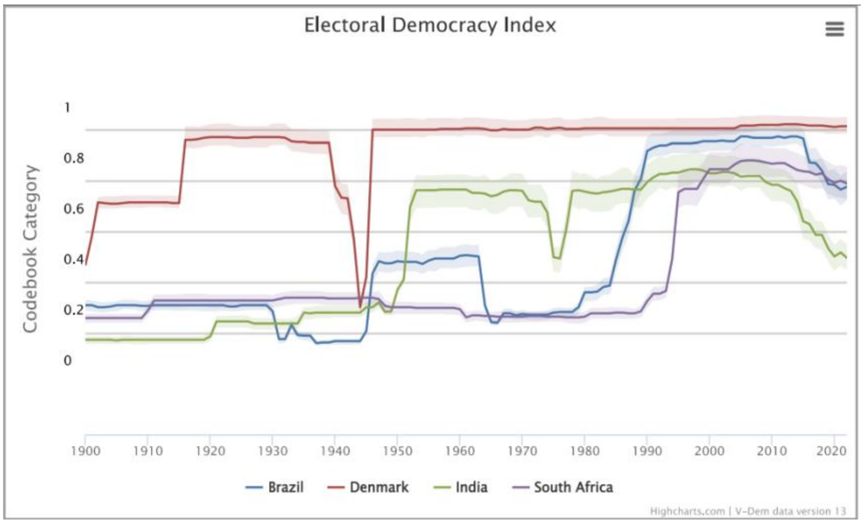

भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां से उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा में स्वस्थ सुधार हो सकता है। अन्यथा, भारत अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता से मुकर जाएगा, और बहुसंख्यक-सत्तावादी व्यवस्था की ओर उतर जाएगा।

फिर, आईपीएमआईई का काम खत्म हो गया है।

एक बार आम चुनाव 2024 अधिसूचित हो जाने के बाद, आईपीएमआईई परिणामों की घोषणा तक चुनाव के सभी पहलुओं की निगरानी शुरू कर देगा। यह प्रक्रिया में निहित किसी भी अनियमितता या कदाचार को भी उजागर करेगा और उनके तत्काल सुधार की वकालत करेगा। इसका लक्ष्य चुनावों का निरीक्षण करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना और चिंताओं को उठाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रहें, लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करें और भारतीय नागरिकों के चुनावी अधिकारों की रक्षा करें।

उसी स्तर पर, आईपीएमआईई सभी भारतीय नागरिकों से इन चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने और जिम्मेदारी से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता है। उसका मानना है कि साथ मिलकर काम करने से भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को बरकरार रखा जाएगा और भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।

7. कार्रवाई के लिए कॉल

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारत की चुनावी प्रणाली, जिसकी लोकतांत्रिक विशेषताएं उचित रूप से स्वतंत्र चुनावी विकल्प सुनिश्चित कर सकती हैं, को बहुसंख्यकवादी नीतियों, कानूनों और सरकारी कार्यों द्वारा खत्म किया जा रहा है। ये अधिनायकवादी विशेषताएँ राजनीतिक पदधारी के लिए सत्ता बनाए रखना आसान बनाती हैं। औसत भारतीय मतदाता, विशेषकर जो अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों से हैं, के स्वतंत्र विकल्प चुनने के अधिकार को बाधित किया जा रहा है। भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर हो सकता है, जहां से वह अपने लोकतांत्रिक चरित्र को पुनः प्राप्त

कर सकता है। हालाँकि, यदि लोकतंत्र की संस्थाएँ, जैसे कि भारत का चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, GE 2024 के दौरान परिणाम देने में विफल रहते हैं, तो बहुसंख्यकवाद के पक्ष में सत्तावादी प्रवृत्ति देश को विपरीत दिशा में ले जा सकती है। इस तरह की चुनावी गिरावट भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की "बुनियादी संरचना" को प्रभावित कर सकती है। इन्हीं कारणों से हम ईसीआई से देश की सर्वोत्तम परंपराओं के अनुसार संवैधानिक जनादेश की रक्षा करने का आग्रह करते हैं।

यह जरूरी है कि ईसीआई इस रिपोर्ट में उठाई गई विशिष्ट चुनौतियों पर ध्यान दे

1. ईसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत दो भागों में विभाजित न हो - एक बहुसंख्यक समुदाय द्वारा आबादी वाला, आम तौर पर उच्च वर्गों और जातियों से संबंधित, और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जाति समूहों और वर्गों से संबंधित:

1. ऐसे देश में समावेशी मतदाता पंजीकरण आवश्यक है जहां विशाल बहुमत गरीब और वंचित है, और 1.4 बिलियन नागरिकों में से 15% से 20% अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जातीय अल्पसंख्यक स्थिति (एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना), आर्थिक नुकसान और गैरमांडरिंग के कारण प्रत्येक मतदाता का स्वतंत्र विकल्प का अधिकार कैसे बाधित होता है। वोट लूटना लोकतंत्र को गिराने का सबसे अच्छा तरीका है। ईसीआई को इस संभावना से बचाव करना चाहिए।

2. हमने देखा कि ईसीआई ने किसी तरह चुनावी बांड (ईबी) के प्रति अपना संदेह खो दिया है। इसके बजाय, इसने ईबी योजना का बचाव करना शुरू कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ईबी निश्चित रूप से राजनीतिक विपक्ष के लिए नुकसानदेह है, तो ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव परिणामों के मध्यस्थ के रूप में वित्तीय लाभ पर काफी हद तक अंकुश लगाया जाए।

3. हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की अखंडता सुनिश्चित करने के प्रति नागरिक समाज समूहों की लगातार मांगों और राजनीतिक विरोध पर ईसीआई द्वारा ध्यान न देने पर गौर किया।

चोरी और ख़राब ईवीएम की समस्या और नतीजों में छेड़छाड़ की संभावना से उत्पन्न चुनौतियों का ईसीआई द्वारा समाधान नहीं किया गया है। ये वास्तविक चिंताएँ हैं। जर्मनी जैसे उन्नत औद्योगिक देश भी इन मशीनों को हैक होने से नहीं बचा सकते। जर्मनी ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है. दूसरों के पास सख्त सत्यापनीयता मानक हैं। वीवीपैट द्वारा छोड़े गए पेपर ट्रेल के साथ सभी ईवीएम उत्पन्न परिणामों के कम से कम 50% को सत्यापित करने की संभावना होनी चाहिए। ईसीआई को यह समझना चाहिए कि ईवीएम/वीवीपीएटी के मौजूदा सत्यापन मानक बेहद अपर्याप्त हैं और इसे काफी हद तक बढ़ाने या पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने की जनता की मांग पर ध्यान देना चाहिए।

4. हमने देखा कि अधिक समावेशी संवैधानिक वादे के लिए लड़ने वाले विपक्षी राजनेताओं और नागरिक समाज पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अनिश्चित शब्दों में हमला किया गया है। विदेशी मुद्रा

विनियमन अधिनियम, राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे कानूनों और एजेंसियों को विपक्षी राजनेताओं और नागरिक समाज के लिए जगह बंद करने के लिए तैनात किया गया है। अक्सर, इन एजेंसियों द्वारा हमला किए गए विपक्षी राजनेता सत्तारूढ़ दल के पक्ष में निष्ठा बदल लेते हैं। इस तरह की धमकी से सत्ताधारी पार्टी मजबूत होती है.' ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा लाभ को कम करने के लिए ऐसी प्रवृत्ति की जांच करनी चाहिए।

5. हमने देखा कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता कैसे ध्वस्त हो गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सूचना तक पहुंच आवश्यक है। न केवल मुख्यधारा के मीडिया पर कब्ज़ा कर लिया गया है, बल्कि डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (2023), दूरसंचार विधेयक (2023) के साथ-साथ सबसे बड़ी संख्या में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन, सिग्नल सूचना नियंत्रण भी शामिल है जो चुनावी पसंद और प्रतिस्पर्धा को अस्थिर कर सकता है। ईसीआई को यह देखने के तरीके ईजाद करने चाहिए कि विचारों की विविधता को इस तरह से स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सके जिससे किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान न हो।

6. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसीआई को स्वयं को विनियमित करने की आवश्यकता है:

मैं। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकारी सत्ताधारी के पक्ष में चुनाव से समझौता न करें, जैसा कि फरवरी 2024 में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था।

द्वितीय. इसे उपरोक्त सभी मुद्दों के संबंध में राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मतदाता पंजीकरण, चुनाव व्यय, ईवीएम का प्रदर्शन, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा धमकी, और मीडिया और सूचना नियंत्रण शामिल हैं।

iii. ईसीआई को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

अनुलग्नक - I

स्वतंत्र और निष्पक्ष (और वास्तविक) चुनाव: अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मानक

इस खंड में, हम चुनावों के लिए मानवाधिकारों के आधार, अंतरराष्ट्रीय कानून की समीक्षा, साथ ही घरेलू कानून के प्रावधानों का पता लगाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। हम भारत में चुनावों पर चुनावी प्रणाली, प्रासंगिक कानूनों और मानदंडों पर भी अधिक बारीकी से नजर डालते हैं, यह समीक्षा करने के लिए कि क्या वे पर्याप्त हैं।

2.1 चुनावों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अवलोकन

चुनाव सहित सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून द्वारा संरक्षित एक मानवाधिकार है। इसकी गारंटी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) और संधि प्रावधानों, मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) द्वारा दी गई है। यूडीएचआर का कहना है कि लोगों की इच्छा सरकार के अधिकार का आधार होगी।

चुनावी प्रक्रियाओं में लोगों की इच्छा का सम्मान करने के लिए मानवाधिकारों का सम्मान आवश्यक है। जैसा कि मानवाधिकार समिति (आईसीसीपीआर की) ने कहा है, "अनुच्छेद 25 लोगों की सहमति के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार के मूल में है"। अधिक विशेष रूप से, “चुनाव लोकतंत्र के केंद्र में हैं, और प्राथमिक साधन बने हुए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। भागीदारी के अधिकार के महत्व को रेखांकित करते हुए यह है कि वे केवल उन सीमाओं के अधीन हो सकते हैं जो कानून द्वारा स्थापित हैं, गैर-भेदभावपूर्ण हैं और उद्देश्यपूर्ण और उचित मानदंडों पर आधारित हैं।

ये अधिकार संविधान सहित भारतीय कानून में भी परिलक्षित होते हैं, जिसकी प्रस्तावना भारत के लोगों द्वारा गणतंत्र बनाने और सभी नागरिकों के लिए न्याय के अलावा स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने की पुष्टि करती है। संविधान के भाग III के तहत समानता (अनुच्छेद 14) और गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) को मौलिक अधिकारों के रूप में और भी सुदृढ़ किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 20) सहित बुनियादी स्वतंत्रताएं, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 32) को लागू करने के उपायों की गारंटी के साथ-साथ अन्य प्रमुख मौलिक अधिकार बनाती हैं। मौलिक अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के केंद्र में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और मानकों में स्वतंत्र और वास्तविक चुनावों के लिए कई बुनियादी मानदंड शामिल हैं। निम्नलिखित अनुभागों में, मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके 'स्वतंत्र चुनाव' और 'वास्तविक चुनाव' दोनों का आगे मूल्यांकन किया जाएगा।

सी. स्वतंत्र चुनाव

स्वतंत्र चुनावों के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि वे 'लोगों की इच्छा' का प्रतिनिधित्व करें (यूडीएचआर अनुच्छेद 21 (3))। इसके अलावा, सभी के लिए वोट के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में भाग लेना खुला होना चाहिए, जो 'आत्मनिर्णय के अधिकार' के केंद्र में है। (यूडीएचआर अनुच्छेद 21(1), आईसीसीपीआर अनुच्छेद 25(ए))। अपनी इच्छा और राजनीतिक राय व्यक्त करने वाले लोगों को स्वतंत्र चुनाव का केंद्र होना चाहिए।

चुनावों में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए और भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। स्वतंत्र चुनाव के मानवाधिकारों को कायम रखने की गारंटी के लिए आठ पूर्वापेक्षित अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता है।

● सबसे पहले, लोगों के खिलाफ कोई भेदभाव शामिल नहीं होना चाहिए और भागीदारी के लिए समान पहुंच प्रदान की जानी चाहिए (यूडीएचआर कला। 2,7; आईसीसीपीआर कला। 2 (1), 3, 26)। उदाहरण के लिए, मतदाता बहिष्कार से बचा जाना चाहिए और चुनावों के लिए सूचना सामग्री भी अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रदान की जानी चाहिए। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बेघरों

और प्रवासियों और विकलांग लोगों जैसे संरक्षित समूहों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ गारंटी प्रदान करें।

● दूसरा, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (यूडीएचआर अनुच्छेद 19, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 19) को बरकरार रखा जाना चाहिए। जबकि राय का अधिकार बिना किसी छूट के पूर्ण है, ऐसे क्षण भी आते हैं जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है जब यह दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है। इन मामलों में, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य आनुपातिक रूप से कार्य करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति से परे है क्योंकि यह संचार, मीडिया, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की स्वतंत्रता का भी वर्णन करता है।

● तीसरा, स्वतंत्र चुनाव के लिए एक और शर्त अधिकार पार्टियों, उनके उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण सभा (यूडीएचआर अनुच्छेद 20, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 22) की स्वतंत्रता है।

● चौथा, संघ की स्वतंत्रता (यूडीएचआर कला. 20, आईसीसीपीआर धारा. 22) राजनीतिक दल बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार देती है।

● पांचवां, आंदोलन की स्वतंत्रता (यूडीएचआर अनुच्छेद 13, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 12) मतदान केंद्रों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है, जानकारी जहां चुनाव होते हैं और उम्मीदवार आंदोलन प्रतिबंधों के बिना अपने अभियान चला सकते हैं।

● छठा, सुरक्षा और डराने-धमकाने से मुक्ति का अधिकार (यूडीएचआर अनुच्छेद 3, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 6, 9) चुनाव संबंधी हिंसा से सुरक्षा का आश्वासन देता है।

● सातवां, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (यूडीएचआर अनुच्छेद 10, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 14) और एक प्रभावी उपाय (यूडीएचआर अनुच्छेद 8, आईसीसीपीआर अनुच्छेद 2 (3) (ए)) स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरणों और शिकायत तक पहुंच प्रदान करता है। मतदाताओं के लिए निवारण निकाय, जो नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के अधिकार के साथ संयुक्त है।

● आठवां, शिक्षा का अधिकार अन्य मानवाधिकारों को जानना और उनका पालन करना मूलभूत आवश्यकता है। राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए राज्य का कार्य अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है।

डी. असली चुनाव

चुनाव को वास्तविक बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तीन प्रक्रियात्मक और तीन परिणाम-उन्मुख मानकों में विभाजित किया गया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के राजनीतिक प्रभाव की निश्चित न्यूनतम मात्रा को स्वीकार और कार्यान्वित किया जाता है।

प्रक्रियात्मक मानक

● आवधिकता और चुनावी समय सीमा के प्रक्रियात्मक मानक में उल्लेख किया गया है कि नियमित चुनाव कराने की आवश्यकता है ताकि लोगों की इच्छा और वर्तमान सरकार के बीच कोई अलगाव न हो (यूडीएचआर अनुच्छेद 21 (3), आईसीसीपीआर अनुच्छेद 25 (बी)). चुनाव केवल सार्वजनिक आपात स्थिति में ही स्थगित किए जाने चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी बदलाव इसमें शामिल सभी लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से होना चाहिए।

● सार्वभौमिक और समान मताधिकार (यूडीएचआर अनुच्छेद 2, 21(3), आईसीसीपीआर अनुच्छेद 2, 25 (बी)) का अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक के वोट को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। यद्यपि मतदाताओं की आयु उनके वयस्कता में लोगों से जुड़ी होनी चाहिए, मानवाधिकार समिति के अनुसार कार्यालय चाहने वालों के लिए आवश्यक आयु अधिक हो सकती है।

● गुप्त मतदान वोट (यूडीएचआर अनुच्छेद 21 (3), आईसीसीपीआर अनुच्छेद 25 (बी)) जो व्यक्ति द्वारा मतदान करने के तरीके के आधार पर जबरदस्ती और धमकी से सुरक्षा से संबंधित है। यह भी पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान गुप्त रहना चाहिए।

परिणामोन्मुख मानक

● पहला परिणाम-उन्मुख मानक वह वास्तविक प्रभाव है जो चुनाव में होना चाहिए। यदि लोगों ने इसके लिए मतदान किया है, तो सत्ता का एक विनियमित हस्तांतरण संभव होना चाहिए और निर्वाचित अधिकारियों को उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो कानून द्वारा उन्हें हस्तांतरित की गई है।

● राजनीतिक बहुलवाद के माध्यम से चुनाव में मतदाता के लिए वास्तविक विकल्प की पेशकश की जानी चाहिए जो तब राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार निर्णय ले सकता है।

● अंत में, पार्टी कार्यक्रमों, उम्मीदवारों और चुनावी प्रक्रिया के बारे में सभी के लिए गैर-पक्षपातपूर्ण जानकारी तक पहुंच के माध्यम से चुनाव के लिए सूचित विकल्प की पेशकश की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रेस को बिना किसी सेंसरशिप के जानकारी मांगने, प्राप्त करने और रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और इस तरह दुष्प्रचार से बचाव करना चाहिए।

2.2 भारत में एफएफई के लिए बुनियादी ढांचा: गारंटी, कानून, प्रक्रियाएं और मानदंड

इस खंड में हम उन कानूनों, प्रक्रियाओं और मानदंडों की जांच करते हैं जो भारत में चुनावों के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं, और क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए यह बुनियादी ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है।

एक। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली चुनाव की फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणाली है, जिसे 'साधारण बहुमत' के रूप में जाना जाता है, जहां एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार सीट जीतता है। . भारतीय संसद के निचले

सदन की संरचना पर संविधान की धारा 81 में कहा गया है कि सदस्यों को राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाएगा, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाले लोग विजेता होंगे।

बी संविधान द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी

संविधान के भाग XV में चुनाव शामिल हैं, अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को चुनाव आयोजित करने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। सभी नागरिकों को, बिना किसी भेदभाव के, मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार अनुच्छेद 325 द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 326 पुष्टि करता है कि वयस्क मताधिकार, या समान वोट, चुनाव का आधार होगा, और अनुच्छेद 327 और 328 संसद और राज्य विधानसभाओं को सशक्त बनाते हैं। क्रमशः निकायों के चुनावों पर कानून बनाना। विशेष रूप से, सिविल अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है (अनुच्छेद 329)।

इ. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951.

भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाला कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए) है, जो भारत की संघीय प्रणाली में राष्ट्रीय संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं दोनों के चुनावों को नियंत्रित करता है। आरपीए अधिनियम स्वयं संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 324 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। आरपीए अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता (और अयोग्यता) (भाग II), चुनावों की अधिसूचना की प्रक्रिया (भाग III), प्रशासनिक मशीनरी की संरचना पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। भारत के चुनाव आयोग से लेकर व्यक्तिगत मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी तक चुनावों का संचालन (भाग IV); राजनीतिक दलों (पार्टी वीए) के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों के अलावा। भाग V चुनाव के संचालन से संबंधित है, जिसमें उम्मीदवारों का नामांकन (अध्याय I), उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के अधिकार और जिम्मेदारियां (अध्याय II), वोटों के मतदान के लिए दिशानिर्देश (अध्याय IV), चुनाव में मतदान के तरीके (अनुभाग) शामिल हैं। 59), और वोटिंग मशीनों का उपयोग (धारा 61ए), उनकी गिनती (अध्याय V) और परिणामों का प्रकाशन (अध्याय VII)। उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों, (अध्याय VIIA) और चुनाव व्यय (अध्याय VIII) की घोषणा के लिए नियम हैं। चुनावों से संबंधित विवादों को संबोधित करने के नियम आरपीए अधिनियम के भाग VI में निहित हैं, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों (अध्याय II/III) के पास है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय (अध्याय IVA) में अपील की जाती है, सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगा दी गई है। चुनावी विवादों में. आरपीए का भाग VII चुनाव में भ्रष्ट आचरण, (अध्याय I) और चुनावी अपराधों (अध्याय II) पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। अंत में, भाग VIII में निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता शामिल है।

डी आदर्श आचार संहिता

भारत में चुनावों के लिए बुनियादी ढांचे का अंतिम तत्व आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) है - जो विशेष रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए प्रासंगिक है। एमसीसी को पहली बार 1968 में सभी राजनीतिक दलों के समझौते के साथ ईसीआई द्वारा अपनाया गया था, ताकि सभी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्तारूढ़

दल को अनुचित लाभ न मिले क्योंकि वह कार्यालय में होता है। चुनाव का समय. एमसीसी को 1991 में अपने वर्तमान स्वरूप में समेकित और पुनः जारी किया गया था।

एमसीसी में आठ भाग होते हैं। भाग I चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अच्छे व्यवहार और आचरण के कुछ न्यूनतम मानकों का प्रावधान करता है। भाग II और III राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने और जुलूस निकालने से संबंधित हैं। भाग IV और V में बताया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान के दिन कैसा व्यवहार करना चाहिए।

भाग VI राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह करता है कि वे अपनी शिकायतें ईसीआई द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के ध्यान में लाएँ। भाग VII सत्ता में पार्टियों से संबंधित है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकार और उसके मंत्रियों से संबंधित कई मुद्दों से संबंधित है, जैसे मंत्रियों का दौरा, सरकारी परिवहन और सरकारी आवास का उपयोग, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाएं आदि। 2013 में एक नया खंड, भाग VIII जोड़ा गया, जो दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव घोषणापत्रों के मुद्दे को नियंत्रित करता है, यह मांग करते हुए कि वे संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुरूप हों, और समग्र रूप से एमसीसी के अक्षरशः और भावना का पालन करें। एमसीसी के पास कोई कानूनी पवित्रता नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संदर्भित किया है। चुनाव निगरानी निकायों के प्रयासों के बावजूद, इसे वैधानिक अधिकार देने में बहुत कम प्रगति हुई है। यह बना हुआ है लेकिन चुनाव अधिकारियों के लिए इसे लागू करना एक आचार संहिता है। इसके मिश्रित परिणाम रहे हैं. फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने फैसले में, जिसे एमसीसी के भाग VIII में दोहराया गया है, अनुच्छेद 324 का हवाला दिया, और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एमसीसी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। जैसा कि आज है, एमसीसी उस दिन से लागू होता है जब भारत का चुनाव आयोग किसी भी चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है, इस चेतावनी के साथ कि ऐसी घोषणा आम तौर पर उस चुनाव की अधिसूचना की तारीख से 3 सप्ताह से अधिक पहले नहीं की जाएगी।